हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 मार्च, 2005

(द्वितीय बैठक)

खण्ड-1, अंक-3

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

मंगलवार, 22 मार्च, 2005

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3) 1
वर्ष 2004-05 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना ।	(3) 47
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।	(3) 47

मूल्य : 17/-

HVS/26/10

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 22 मार्च, 2005 (दूसरी बैठक)

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान मंडल, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार एच०एस०चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion on Governor's Address will be resumed. Shri Naresh Malik was on his legs when the House adjourned at 1.30 P.M. today and he may continue his speech.

श्री नरेश मलिक (हसनगढ़) : स्पीकर सर, इस सरकार के गठित होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी भजन लाल जी ने एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया था कि पिछली सरकार ने जितने भी कर्मचारियों की छंटनी की है उन्हें सेवा में वापिस लिया जाएगा। कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष ने यह वायदा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सभी पुलिस कर्मचारी और जितने भी छंटनीग्रस्त अधिकारी/कर्मचारी हैं सब को वापिस लिया जाएगा, इस आश्वासन के बारे में सरकार विचार करे और सदन को अवगत करवाए। स्पीकर सर, आज सरकार बदल गई है लेकिन पूर्व व्यवस्था आज भी नहीं बदली है। आज ही कांग्रेस के मेरे एक वरिष्ठ साथी ने बताया है कि ट्रैफिक पुलिस, जिसका काम रोड ट्रैफिक को सुचारू करना है आज भी वह एक्साईज़ का काम कर रही है। ट्रकों को रोकना और उनसे धन उगाहना आज भी यही स्थिति है। ट्रैफिक पुलिस में आज भी इस तरह की बात चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं।

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं तथा इनको बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार के वक्त के जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्ज थे, जिनकी ये चर्चा कर रहे हैं, हमारी सरकार ने आते ही उन सब को पदमुक्त कर दिया है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अब यह सारा चार्ज एस०डी०ओ० (सिविल) के पास है।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि मात्र एक हफ्ता पहले मेरी फैक्टरी के दो ट्रक सामान लेकर गए थे जिनके बिल और कागज बाकायदा सब कुछ ठीक था उनसे फिर भी तीन हजार रुपये ऐंठे गए हैं। मेरे आदमियों ने गलती यह की कि उन्होंने पुलिस वालों के नम्बर नोट नहीं किए। स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं यह जिक्र करना चाहूंगा तथा सरकार से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या सरकार नए और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्यवाही करेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहूंगा कि जो पुराने उद्योग आज बन्द पड़े हुए हैं चाहे वे कर्ज के कारण पड़े हैं या किसी और कारण से बन्द पड़े हुए हैं क्या उन उद्योगों को फिर से चलाने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है या सरकार इस बारे में कुछ विचार कर रही है। जो उद्योग बन्द पड़े हैं क्या सरकार कोई सहायता दे कर या कुछ देकर उन उद्योगों को चालू करवाने की कोई कोशिश करेगी। स्पीकर सर, शिक्षा के बारे में पिछली सरकार ने जो नीतियां अपनाई थीं वह ठीक नहीं थी, चाहे मिडल स्कूल्ज थे या प्राईवेट हाई स्कूल्ज थे और जितने भी अन्य स्कूल्ज थे उनकी आर्थिक हालत

[श्री नरेश मलिक]

बहुत खराब थी और उनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही थीं। वे लोग माननीय ऐजुकेशन मिनिस्टर जी से मिले भी हैं। पिछली सरकार के गलत रवैये ने उन्हें परेशान किया है। स्कूलों की हालत ठीक करने के बारे में सरकार विचार करे। आज हम कहते हैं कि सदन में विपक्ष नहीं है *** ****

Mr. Speaker : No. No. This is not the way. This is not to be recorded. Mr. Malik, your time is over. Please take your seat. (Interruptions) Please conclude your speech in one minute.

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, इस समय माननीय फाईनैंस मिनिस्टर जी हाउस में बैठे हुए हैं इसलिए मैं साम्पला में दीनबन्धु सर छोटू राम अकादमी के बारे में अपनी बात को रिपीट कर देता हूं क्योंकि जिस समय मैंने पहले इसका जिक्र किया था उस समय माननीय फिल मन्त्री जी हाउस में नहीं थे। पिछली सरकार ने साम्पला में एक स्कीम लागू की थी कि पूरे साम्पला गांव और गढ़ी गांव को एक आदर्श गांव बनाया जाएगा। पिछली सरकार ने इसके बारे में घोषणा की थी और अब भी उसका कार्य चल रहा है। माननीय वित्त मन्त्री जी दीनबन्धु सर छोटू राम जी के नाते से भी हैं, मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे इस योजना को शीघ्र पूरा करवाएं। स्पीकर सर, पिछले कल सदन में यह बात चली थी कि गोवा में हाऊस का कैपचर हो गया और झारखण्ड में कैपचर हो गया । मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा में इनकी इतनी मैजोरिटी है कि यहां पर हाउस कैपचर नहीं होगा। स्पीकर सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी सीट पर बैठता हूं।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल (अम्बाला कैंट) : स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसके बाद मैं राज्यपाल महोदय का और पार्लियामैंट्री मिनिस्टर का तथा दूसरे साथियों का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें हरियाणा में होने वाले कामों के बारे में अवगत करवाया। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूं कि 6 महीने पहले अम्बाला छावनी में फल्ड आया था और वहां पर सैंकड़ो-हजारों करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ था। उस फल्ड के दौरान अम्बाला छावनी में रिहायशी इलाकों की कोई गली और इन्डस्ट्रीज ऐसी नहीं थी जहां पर पानी नहीं आया था, उस समय पानी की वजह से वहां पर काफी नुकसान हुआ था। पिछली सरकार ने अम्बाला छावनी को बाढ़ग्रस्त एरिया घोषित नहीं किया था जिसकी वजह से वहां पर चाहे निम्न स्तर के लोग थे, मिडिल स्तर के लोग थे या उच्च वर्ग के लोग थे या अन्य लोगों का जो भी नुक्सान हुआ था उसका उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाया था जबकि वे मुआवजे के हकदार थे। मेरा सरकार से निवेदन है कि अम्बाला छावनी को बाढ़ग्रस्त एरिया घोषित करके उसका दोबारा से सर्वे करवाकर सभी वर्गों के लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान किया जाए। स्पीकर सर, इसके साथ मैं सदन में यह भी बताना चाहूंगा कि पहले अम्बाला छावनी में संसार में साईंटिफिक इन्स्ट्रूमैंट्स का एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब पिछले 10 सालों से अम्बाला छावनी में साईंटिफिक इन्स्ट्रूमैंट्स इन्डस्ट्री का नामोनिशान नहीं है। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि अम्बाला छावनी में इन्स्ट्रीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिक पड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि सरकार कुछ ऐसे स्टैप्स उठाए जिससे अम्बाला छावनी की इन्डस्ट्री अपलिफ्ट

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

हो और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके तथा अम्बाला छावनी में इम्पलायमैंट बढ़ सके। स्पीकर सर, हरियाणा में प्रापर्टी बेचने के लिए कहीं पर भी नो-आब्जैक्शन सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन पिछली सरकार ने इसको अम्बाला छावनी में ही इम्पलीमैंट कर दिया था। नो-आब्जैक्शन सर्टिफिकेट लेने के नाम पर पिछली सरकार लोगों से हजारों रुपए लेती रही है। प्रापर्टी को बेचने के लिए नो-आब्जैक्शन सर्टिफिकेट लेना पूरे हरियाणा में सिर्फ अम्बाला छावनी में ही है। यह नीति पिछली सरकार ने जनता को परेशान करने के लिए बनाई थी। मेरा सरकार से निवेदन है कि नो-आब्जैक्शन सर्टिफिकेट लेने की नीति को खत्म किया जाए। स्पीकर सर, जिस आदमी के घर में बेटी की शादी हो और उसके लिए उसको अपनी एक लाख की प्रापर्टी बेचनी है तो उससे 20-20 हजार रुपए नो-आब्जैक्शन सर्टिफिकेट देने के नाम पर लिए जाते रहे हैं। अगर किसी आदमी के पिता जी बीमार हैं और उसको उनके ईलाज के लिए पैसे की जरूरत है अगर उसको अपनी प्रापर्टी बेचनी पड़ती है तो उससे भी 15-15 हजार रुपये नो-आब्जैक्शन सर्टिफिकेट देने के नाम पर लिए जाते रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस नीति को जो पिछली सरकार ने शुरू की थी इसको बंद किया जाए। जो कंडीशन पिछली सरकार ने लगाई थी वह गैर कानूनी है। किसी भी म्यूनिसिप्ल एक्ट के किसी भी सैक्शन में और किसी भी क्लॉज में ऐसा कहीं पर भी मैंशन नहीं है एन०ओ०सी० लेने की कोई आवश्यकता है। इसके अलावा अम्बाला छावनी के अन्दर जो प्राईवेट स्कूल्ज़ हैं उनसे पहले कांग्रेस सरकार के वक्त में 700 रुपए सालाना लीज के रूप में लिए जाते थे। पिछली सरकार के वक्त में उन स्कूलों पर लीज़ की रकम 25-25 और 30-30 लाख रुपए सालाना कर दी गई है। यानि की चार-चार हजार गुणा लीज़ बढ़ा दी गई थी। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो प्राईवेट स्कूल हजारों बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं उनको राहत देने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं। पिछली सरकार ने एक ऐसी घोषणा की थी कि प्राईवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसा न किया जाए क्योंकि प्राईवेट स्कूल ही हरियाणा में जनता को प्रोपर एजुकेशन दे रहे हैं। हरियाणा में 30 लाख स्टूडैंटस ऐसे हैं जो प्राईवेट स्कूलों से एजुकेशन ले रहे हैं । स्पीकर सर, पूर्व सरकार ने अपने मोटिव के लिए और अपने परप्पज़ को हल करने के लिए ऐसे स्टैप उठाए ताकि वे अपनी मन्थली इन्कम का सोर्स बना सकें। अब नया सैशन शुरू हो गया है और एडमिशन शुरू हो गई हैं लेकिन बच्चों के सामने और टीचर्ज के सामने समस्या आ रही है कि कहीं ये स्कूल बंद तो नहीं हो जाएंगे। इसलिए मेरी सरकार से पुरजोर प्रार्थना है कि स्कूलों की और बच्चों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार तुरन्त उचित कदम उठाये ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बात अपने हल्के की सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे हल्के में सबसे बड़ी प्राब्लम सड़कों की है। पिछले दस सालों में वहां की सड़कें खत्म हो चुकी हैं। उनमें इतने बड़े-बड़े गढ्ढे हो चुके हैं कि अगर कोई स्कूटर ड्राईवर वहां पर गिर जाता है तो या तो ड्राईवर को निकालना पड़ेगा या फिर स्कूटर को निकालना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि सड़कों को बनाने के लिए जो बजट दिया गया था वह कहां गया । मेरा निवेदन है कि मेरे हल्के की सड़कों को तुरन्त ठीक कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला छावनी के अंदर गंदगी इतनी ज्यादा फैल गयी है कि अगर उसको फैलने से रोका नहीं गया तो अम्बाला छावनी के साथ-साथ आसपास के दूसरे एरियाज में भी पीलिया फैल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

Shri S.S. Surjewala : Sir, I want to speak on a point of order. Please educate the new members becasue they are not speaking relevant. It seems that they are not speaking on the Budget.They should speak on the policy and on the Governor's Address. I do not want to interrupt. I want to say that they may please be educated. Policy matters should be discussed. The individual questions regarding constituency can be discussed at other time.

डा० सीताराम (एस०सी०, डबवाली) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए समय दिया उसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण में आने वाले समय के लिए सरकार की नीतियों के बारे में एवं सरकार हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा किस प्रकार करेगी, किस प्रकार से विकास के कामों को अंजाम देगी, को दर्शाया गया है। इसके अंदर कृषि क्षेत्र के बारे में भी चर्चा की गयी है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की जो 70 प्रतिशत जनता है वह कृषि के ऊपर ही आधारित है और अपना रोजगार वह कृषि ही से चलाती है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक और बात पर जोर दिया गया है और वह बात है कि कृषि का विविधीकरण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि कृषि का विविधिकरण किया जाना चाहिए लेकिन इसके लिए सरकार किसानों को क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाएगी, किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम लाभकारी मूल्य किस प्रकार दिया जाएगा एवं फसलों की खरीद उचित समय पर हो सके क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी ताकि जो किसान अपनी फसल चक्र को बदलने का प्रयास करेंगे उनको किसी भी प्रकार का घाटा न उठाना पड़े। कोई ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए जिससे किसान परेशान न हों लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर ऐसा कोई ठोस उपाय इस बारे में नहीं दर्शाया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो इलाका है वह कॉटन बैल्ट का इलाका है। यहां पर इस बार कॉटन की बम्पर क्राप हुई है लेकिन जो केन्द्र सरकार की सी०सी०आई० नाम की एजैंसी है उसने कॉटन का जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया वह बहुत कम किया है। अध्यक्ष महोदय, कॉटन की फसल की कृषि करने के लिए काफी खर्चा आता है लेकिन न्यूनतम मूल्य पर भी किसानों की इस फसल को वहां पर नहीं खरीदा गया। किसान मंडी के अंदर 15-15, 20-20 दिन अपनी फसल को बेचने के लिए बैठे रहते थे। (विघ्न) ठीक है, सरकार जरूर हमारी थी लेकिन वह एजैंसी तो केन्द्र सरकार की है और वही इस फसल की खरीद करती है। केन्द्र में तो आपकी सरकार थी अगर आप चाहते तो उन किसानों को न्यूनतम मूल्य से ज्यादा दाम दिलवा सकते थे और समय पर उसकी खरीद करवा सकते थे लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने वायदे तो किए लेकिन उन बातों को अंजाम देने में आप नाकाम रहे। अध्यक्ष महोदय, फसलों के विविधीकरण की जो बात कही गई है उस बारे में मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ठोस कार्य और उपाय किए जाएं ताकि किसान फसलों के विविधीकरण की ओर आकर्षित हो सकें और उसे घाटा न उठाना पड़े। आज के जमाने में खेती कोई लाभकारी व्यवसाय नहीं रह गया है। आज किसान की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए इस सरकार को और अच्छे कदम उठाने चाहिएं। किसान पर ओलावृष्टि की प्राकृतिक मार भी पड़ी है जिसके अंदर फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा है कि ओलावृष्टि के लिए सरकार ने मुआवजा राशि देने की घोषणा की है और स्पैशल गिरदावरी की घोषणा की है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी जब विपक्ष में थे तब उन्होंने ओलावृष्टि के लिए प्रति एकड़ दस हजार रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग की थी। आज उनकी

सरकार है मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि अब वे अपनी बात को लागू करवाने का प्रयास करेंगे। (विघ्न) मैं तो वही बात कह रहा हूं जो कि उन्होंने कही थी । नहरी पानी के समान वितरण के लिए भी आदरणीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर जिक्र किया गया है। जब हरियाणा प्रदेश बना उस समय भी कांग्रेस का शासनकाल था। उस समय से पानी की वितरण प्रणाली चली आ रही है। बीच में थोड़े समय के लिए हमारा शासन आया। इस दौरान हमने उस वितरण प्रणाली के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। अब नहरी पानी का वितरण सरकार किस तरीके से करेगी ? क्या उत्तरी हरियाणा के पानी का हिस्सा काटकर किसी और दूसरे हिस्से को दिया जाएगा? इसके बारे में सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, 100-100 डायरैक्ट मोगे नहरों से लगा रखे हैं जो कि लगा नहीं सकते हैं और इनके यहां एक-एक फार्म पर पूरा पूरा रजबाहा चल रहा है। (विघ्न)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सिंचाई के लिए दादूपुर नलवी नहर का भी जिक्र किया गया है। यह कार्य भी हमारी सरकार के समय में मंजूर किया गया था। इसमें ऐसा नया कुछ भी नहीं। दूसरे इस अभिभाषण में एस०वाई०एल०नहर का जिक्र किया गया । इसके बारे में आदरणीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर स्पष्ट नहीं बताया गया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कब तक लागू करवाएगी क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है और केन्द्र में भी कांग्रेस गठबंधन की सरकार है । मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से यह कार्य अब रुके इसलिए एस०वाई०एल०नहर का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाना चाहिए। अभिभाषण में यह भी नहीं बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इस नहर को बनवाएंगे या बातचीत के माध्यम से इसको बनवाने का काम करेंगे। अभिभाषण में कहीं भी नहीं दर्शाया गया कि नहर के काम को पूरा करने के लिए पैसे का प्रबन्ध कैसे किया जायेगा। इसके अलावा इस अभिभाषण के अन्दर यह जिक्र किया गया है कि नई औद्योगिक पोलिसी बनाई जायेगी परन्तु यह जिक्र नहीं किया गया कि पिछली सरकार की जो औद्योगिक पोलिसी थी उसमें क्या कमियां थीं। यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस तरह से उद्योग को बढ़ावा दिया जायेगा। इस अभिभाषण में कहीं भी यह स्पष्ट नजर नहीं आता जिससे हमें यह विश्वास हो जाये कि हरियाणा में और ज्यादा उद्योग लगा सकते हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के व्यापारिक वर्ग से यह वायदा किया था कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर कांग्रेस की सरकार आयेगी तो वैट प्रणाली को तब तक लागू नहीं किया जायेगा जब तक सारे भारतवर्ष में यह प्रणाली लागू नहीं हो जाती । इसके बारे में भी अभिभाषण में कोई स्पष्ट बात नहीं की गई कि यह सरकार उस वायदे को पूरा करेगी या नहीं।

Mr. Speaker : Please wind up, Dr. Sahib.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, आज के दिन बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। चुनाव के समय यह वायदा किया गया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार आयेगी तो बेरोजगारी की समस्या को हल कर देंगे। मुझे लगता नहीं कि इस सरकार के पास कोई जादुई छड़ी होगी जिससे इस समस्या का समाधान कर देंगे। सरकार इस समस्या को हटाने का काम करेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ हरियाणा प्रदेश के अन्दर नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष में है। इसको दूर करने के लिए राज्यपाल के अभिभाषण में कोई विशेष रूप से जिक्र नहीं किया गया है।

Mr. Speaker : Please wind up.

डा० सीता राम : बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो पूरे भारतवर्ष के अन्दर है। आज जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कोई नीति बनायेगी या जनसंख्या वृद्धि को कम करने का कोई काम करेगी ? इसके इलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं उसके बारे में क्या सरकार कोई ऐसे कदम उठायेगी कि गांवों के लोगों को गांव के अन्दर ही वे सब सुख सुविधाएं दी जा सकें जो शहर के लोगों को मिलती हैं ताकि वे शहरों की ओर पलायन करना बन्द कर दें।

Mr. Speaker : Please wind up.

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के डबवाली में जो विकास कार्य पिछली सरकार के समय में शुरु हुए थे मैं चाहता हूं कि इस सरकार में भी वे विकास कार्य बिना किसी भेदभाव के पूरे किये जायें क्योंकि उन कामों के लिए पैसा सैंक्शन हो चुका है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए खुला समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

Mr. Speaker : Thank you very much Dr. Sahib. Please take your seat.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Speaker Sir, as Shri Shamsher Singh Surjewala ji, senior member of the House has also pointed out that if you want a tone to be set for the newly elected members, you must give some time to senior member after two members because they are to draw inspirations from senior members.

Mr. Speaker : Yes, Mr. Birender Singh ji, I am doing that.

Sardar Paramvir Singh (Tohana) : Sir, I want to thank his excellency the Governor of the Haryana for his address to this House citing priorities of the Congress Government. I also want to congratulate the Congress Government of Haryana for having visionary approach and touching problems of all sections of the society with deep understanding and having a commitment of all around development of the State. The development should not be in one particular area like we saw earlier. I mean lop sided approach, what we saw earlier and we have been absolutely myopia vision of the previous Government with regard to development. The previous Government made the enormous wastage of Public funds. I will say, not even 30% of the grants on the ground level were utilized. Rest of the grants were misappropriated and it should be enquired into. I want to draw the attention of the Government for the loss suffered by the farmers due to hailstorm and the compensation was disbursed just one day before the counting of votes on 26th February, 2005. Many genuine people were left out from the compensation. If genuine people are left out, it should be checked again. Recently the loss has been incurred by the seasonal rain and high velocity wind, which has caused loss to the standing wheat crop. The loss should be assessed and the farmers should be given relief. Thank you.

श्री दान सिंह (महेन्द्रगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे गरिमापूर्ण सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए

समय दिया और साथ ही सभी नव निर्वाचित विधायकों को बधाई देता हूं और मैं प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रदेश को भ्रष्टाचार और भय और आतंक के माहौल से मुक्ति दिलाई । अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के अन्दर सरकार की मंशा के बारे में राज्यपाल महोदय ने बहुत कुछ बताया है। पिछले पांच-साढे पांच वर्ष के अन्दर इस प्रदेश की व्यवस्थाएं चरमरा गई थीं व आम आदमी का प्रजातंत्र से विश्वास उठ चुका था। मैं इस प्रदेश की जनता को विशेष तौर पर बधाई देता हूं जिन्होंने इस बात का अहसास किया और प्रजातांत्रिक तरीके से सारे माहौल को एक क्षण में पलट कर के रख दिया। आज प्रदेश के लोगों को आशाएं थी, आकाक्षाएं थी कि नई सरकार आएगी और नई नीतियां लेकर आएगी और उन्हीं नीतियों का उल्लेख राज्यपाल महोदय जी ने अपने अभिभाषण में किया है। बहुत सी चीजों के बारे में इस अभिभाषण के अन्दर बताया गया है । कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज नई सरकार ने की है, जिन के बारे में मैं सरकार को और विशेषकर मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। हमारा यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां के लोगों की मुख्य अजीविका कृषि पर निर्भर करती है। मैं समझता हूं कि राज्य की अर्थ व्यवस्था का मूल आधार भी कृषि है, इस कृषि के क्षेत्र के अन्दर जो सरकार ने नीति अपनाई है वह काबिले तारीफ है इस बात की ही दक्षिणी हरियाणा के लोग सालों से अपेक्षा करते थे हरियाणा प्रदेश बनने के बाद एक तरफ तो कुछ क्षेत्रों ने सूखे की मार झेली है और दूसरी तरफ इसी प्रदेश का क्षेत्र ज्यादा पानी आ जाने से सेम की मार झेल रहा था। एक तरफ तो सेम की समस्या से निपटने के लिए पैसे का प्रावधान करना पड़ता था और दूसरी तरफ हमारे क्षेत्र में सूखा पड़ा था, हमारे क्षेत्र में लोगों ने पानी के लिए 1400 फुट गहराई तक खुदाई की । इतनी गहरी खुदाई के बाद वहां पानी मिला भी तो वह भी खारा पानी और बहुत कम मात्रा में। आज मुख्यमंत्री महोदय और सरकार ने एक ऐसी आशा की किरण हममें जगाई है कि जो पानी आज हरियाणा में मौजूद है उसका समान और न्यायोचित बंटवारा किया जाएगा। इसके लिए मैं सरकार और विशेषतौर पर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने आते ही हमारी उस समस्या की तरफ ध्यान दिया। साथ ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हम भी उस क्षेत्र के वासी हैं जहां पानी बहुत कम है उसके रिचार्ज की तरफ भी ध्यान देकर मौजूदा सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जहां तक एस०वाई०एल०की बात है, एस०वाई०एल० को जीवन रेखा तो सभी कहते रहे हैं लेकिन उसका पानी हमें किस तरह मिले, इस तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया और न ही पानी लाने के लिए ठोस प्रयास किए गए। हमारी मौजूदा सरकार ने आते ही उसको प्राथमिकता दी है। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि से जुड़ी हुई है और हमारा पुरजोर प्रयास रहेगा कि हम केन्द्र के नेताओं से मिलकर, अपने बड़े भाई पंजाब के नेताओं से मिलकर एस०वाई०एल०का पानी इस पंचवर्षीय योजना में हरियणा प्रदेश में लेकर आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, कृषि बिजली पर निर्भर करती है और दक्षिणी हरियाणा के किसान तो पूरी तरह से बिजली पर ही निर्भर रहते हैं। सरकार ने आते ही बिजली की कीमतों को सुधारने के लिए जो प्रयास किये हैं उसको देखते हए जो सालों साल से बिलों की रिकवरी पैंडिंग पड़ी थी उसके ऊपर भी सरकार ने चेतना और चिंता जताई है। हमें आशा है कि बिजली के जो बिल किसानों के बकाया पड़े हैं उनका हल निकालने के लिए न्यायोचित, बायबल सोर्सिज ढूंढने पर सरकार विचार करेगी जो कि बहुत अच्छी शुरूआत होगी । अध्यक्ष महोदय, किसानों के ऊपर लाखों रुपये के बिजली के बिल बकाया हैं। कृषि की कमाई से किसान वे बिल पे नहीं कर सकते। पहले वाली सरकार के समय में जब कोई ट्रांस्फार्मर जल जाता था तो किसान को कहा जाता था कि पहले पैंडिंग बिल जमा करवाओ उसके बाद ट्रांस्फार्मर बदला जायेगा जिस कारण किसान की

[श्री दान सिंह]

खड़ी फसल पानी के अभाव में नष्ट हो जाती थी। इस तरह से जुल्म पिछली सरकार के समय में किसानों पर होते थे। हम अपनी सरकार से आशा करते हैं कि इसका भी न्यायोचित हल बहुत जल्दी सरकार निकालेगी ताकि किसान आने वाले समय में बकाया बिलों का भुगतान करके नये बिलों को समय पर जमा करवा सकें। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विकास के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है। यह बात ठीक है कि हरियाणा के लिए कहा जाता है कि there is no agriculture except culture. हम कृषि पर निर्भर करते हैं लेकिन किसी भी प्रदेश का बहुमुखी विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें उद्योगों को साथ लेकर नहीं चला जायेगा। हरियाणा के अंदर पिछले पांच सालों के अंदर जिस तरह का माहौल था उससे सभी उद्योगपति इतना घबराये हुए थे कि वे अपने-अपने उद्योगों की न केवल यहां से पलायन की बातें करते थे बल्कि आने वाले उद्योगपतियों को भी कहते थे कि वे तो यहां फंस चुके हैं तुम यहां आकर गलती मत करना। सरकार की गलत नीति की वजह से हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। हमारा प्रदेश तीन तरफ से दिल्ली से लगता है। इस प्रदेश की भौगोलिक और औद्योगिक स्थिति इस तरह की बन सकती थी कि दुनियां में हम एक नम्बर पर हो सकते थे। अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव जैसी नगरी जहां पर सर्वप्रथम एक मारूति उद्योग आया था आज उसकी वजह से हम अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर चले गये हैं। इसी तरह से और भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस प्रदेश के अंदर आयें तो इस प्रदेश के बहुमुखी विकास में और अर्थव्यवस्था में दिन रात का फर्क पड़ सकता है। मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहां उद्योग लगाने के लिए सुविधाएं दें। गुड़गांव की तरह ही हमारे महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी जैसे पिछड़े इलाकों में भी उद्योग लगायें जायें। उद्योग लगने से जहां प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा का सवाल है, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब तक प्रदेश का हर नागरिक शिक्षित नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता के साथ हम न्याय नहीं कर पायेंगे। अगर व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेता है। आज शिक्षा को कमर्शियल ओरियंटिड करके रख दिया है। अभी किसी साथी ने प्राईवेट स्कूलों का जिक्र किया। मैं मानता हूं कि सरकारी शिक्षा संस्थानों के अंदर उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करवाई जाती जितनी प्राईवेट स्कूलों में करवाई जाती है। लेकिन हर व्यक्ति अपने बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता और न ही वह उनकी फीस वहन कर सकता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार की तरफ से अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षा संस्थानों का प्रावधान किया जाये जिनमें अच्छी पढ़ाई हो और गरीब बच्चे उनमें अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में समानता के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। दक्षिणी हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में आज तक उपेक्षित रहा है। वहां पर न तो मैडिकल कालेज है, न इंजीनियरिंग कालेज है, न कोई विश्वविद्यालय है और न ही किसी विश्वविद्यालय की वहां ब्रांच है। अगर मुख्यमंत्री जी और सरकार चाहे तो प्रदेश की समानता को देखते हुए दक्षिणी हरियाणा के अंदर एक विश्वविद्यालय अवश्य दे ताकि यहां के लोग शिक्षा से वंचित न रहें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहूंगा । किसी भी प्रदेश की सबसे बड़ी धरोहर उस प्रदेश के स्वस्थ नागरिक होते हैं। मैं समझता हूं कि अगर किसी प्रदेश के नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे तो वह प्रदेश आगे नहीं जा सकता । पिछले पांच सालों में प्रदेश के अन्दर जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। सरकारी अस्पताल में अगर जाते थे तो वहां पर या तो डाक्टर्ज नहीं मिलते

थे या फिर दवाई नहीं मिलती थी। दवा मिलती थी तो बड़े भारी पैसे वाली ऐसी दवाई लिख दी जाती थी जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है। जिन कम्पनियों की दवाईयों पर डाक्टर्ज को कमीशन अधिक मिलता था उन कम्पनियों की बनी दवाई लिख दी जाती थी। अस्पताल में बीमारियों के टैस्टों का भी कोई इन्तजाम नहीं है। बीमारियों के सारे टैस्ट सरकारी अस्पताल में न होकर प्राईवेट लैबज में होते थे। मौजूदा सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य की तरफ चिन्ता जताते हुए प्रदेश के हर नागरिक को अच्छी चिकित्सा सुविधा देने की बात कही है ताकि आगे आने वाले समय के अन्दर न केवल हमारे नागरिक स्वस्थ हों बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी हमारे प्रदेश के बारे में पूरे देश के अन्दर चर्चा की जा सके। अध्यक्ष महोदय, जो स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए हैं मैं समझता हूं कि उनमें एम०एल०आर० काटने के अलावा कुछ नहीं किया जाता। चाहे 325 का केस है या 326 का केस है, इस तरह के केसिज वहां पर दर्ज होते रहे हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों की इस प्रकार की मानसिकता से लोग ग्रस्त रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिन कमियों का सरकार अहसास कर रही है निश्चित तौर पर उन कमियों को दूर करने पर सरकार ध्यान देगी। अब भविष्य में हस्पतालों के अन्दर एम०एल०आर० काटने के बजाय लोगों का उपचार होगा। लोगों का उपचार होगा तो तभी हम लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इन सब बातों की तरफ ध्यान देगी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं जनस्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहूंगा। जनस्वास्थ्य के प्रति भी प्रदेश के कई हिस्से पिछली सरकार में उपेक्षित रहे हैं जहां पर आज तक मिनिमम हाईजेनिक कंडीशन भी पूरी नहीं की गई। इस बारे में मेरा कहना है कि मेरा क्षेत्र विशेष तौर पर ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें जन स्वास्थ्य सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है। जब सरकार सारे प्रदेश के लोगों की सुख सुविधा के बारे में सोचती है तो सरकार को उन क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए जिन क्षेत्रों की तरफ पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। डाक्टर साहब अभी बोलते हुए कह रहे थे कि लोगों का पलायन गांवों से शहरों की तरफ और कस्बों की तरफ हो रहा है। यदि शहरों वाली सुविधा गांवों के स्तर पर या कस्बों के स्तर पर मिलेगी तो यह पलायन की प्रवृत्ति स्वत: रुक जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार को पुन: बधाई देता हूं और यह आशा और अपेक्षा रखते हुए कि जो बातें अभिभाषण के माध्यम से लोगों के सामने रखी हैं उनको सरकार पूरा करेगी ताकि जिस भावना से लोगों ने हमें जनप्रतिनिधि चुन करके भेजा है उनकी यह भावना पूरी हो सके, धन्यवाद।

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो समाज है यह पुरुष प्रधान समाज है। हरियाणा में खासतौर पर महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। डावरी और डोमेस्टिक वायलैंस के केस हम रोजाना देखते और सुनते हैं। हम यहां पर एक तरफ महिला सशस्त्रीकरण यानि वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे हरियाणा में लड़कियों की संख्या लड़कों के अनुपात में कम होती जा रही है। इसके लिए हमारे कई लाज़ बन चुके हैं किन्तु इनको किसी ने स्ट्रिकटली फालों नहीं किया। स्पीकर साहब, हमें इस दिशा में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यह सोचकर रोंगटे खड़े होते हैं कि अगर इसी प्रकार से लड़कियों की संख्या कम होती गई तो कल को हमारी बहू-बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जायेगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे इतने भाइयों ने अपनी अपनी बात कही लेकिन एक दो को

[श्रीमती सुमिता सिंह]

छोड़कर किसी ने भी महिलाओं की बात नहीं उठाई। महिलाओं की कुछ ऐसी बेसिक नैसेस्टिज हैं जिनको पूरा करना आवश्यक है। जैसे कि शौचालय हैं, आप किसी गांव में चले जाएं तो वहां पर 70 परसेंट महिलाओं के लिए शौचालय नहीं हैं। शौचालय न होने के कारण उनको बहुत मुश्किल होती है। वे शौच के लिए या तो सुबह 4.00 बजे उठकर जाती हैं या रात के अन्धेरे में जाती हैं। आपने भी देखा होगा कि रात के समय लड़कियां जब शौचालय के लिए घर से निकलती हैं तो बहुत सी लड़कियों के साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं और वित्त मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं। मैं इस बारे में इनसे निवेदन करूंगी कि जब हमारा अगला बजट आए तो उसमें महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनके लिए खास प्रावधान रखा जाए। महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सी स्कीम्ज हैं जो महिलाओं के लिए आती हैं। वे स्कीम्ज उन महिलाओं के लिए होती हैं जो शिक्षित नहीं हैं या जो पावर्टी लाईन के नीचे रहती हैं । वे इन स्कीम्ज का फायदा नहीं उठा सकती क्योंकि इन स्कीमों के बारे में न तो उनको कोई ठीक तरह से बताता है और न ही कोई समझाता है। इसके लिए अगर हो सके तो हमें सिंगल विन्डो सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कुछ एन०जी० ओज० भी हों और कुछ एम्पलाईज भी हों जो वहां पर उसी स्थान पर महिलाओं से संबंधित जितनी भी स्कीम्ज हैं उनकी जानकारी दे सकें। ओल्ड एज पैंशन की स्कीम है या कुछ ऐसी स्कीम्ज हैं जहां पर महिलाओं को लोन्ज दिया जाता है या रोजगार देने के लिए अथवा अपना छोटा मोटा काम करने के लिए जानकारी दी जाती है। इन सबकी जानकारी देने के लिए सिंगल विन्डो सिस्टम होना अनिवार्य है। जिससे महिलाएं उन स्कीमों का फायदा उठा सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि हमारे बहुत से भाई-बहन बोलना चाहते हैं। हम कहते हैं कि लड़कियों की शिक्षा फ्री है लेकिन इसमें भी बहुत सी कमियां हैं। हम लोग जब गांवों में जाते हैं तो लड़कियां और उनके मां-बाप यह कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए कहने को तो शिक्षा फ्री है लेकिन इसमें कई ऐसी चीजें लगा दी जाती हैं कि वे लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं जैसे बिल्डिंग ऐलॉटमैंट के लिए कुछ पैसा लेते हैं या कुछ और दूसरी चीजों के लिए पैसा लेते हैं जिससे शिक्षा फ्री नहीं रहती है। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिसमें लड़कियों को दी जाने वाली शिक्षा पर उनको खर्च न करना पड़े बिल्कुल फ्री ऐजुकेशन हो और उनको किताबें व दूसरा सामान फ्री मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह कर आपका धन्यवाद करती हूं और अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री नरेश यादव (अटेली) : आदरणीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो नई सरकार को मैं बधाई देता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार पहले भी रही है लेकिन पहली बार इस सरकार ने यह माना है कि पानी के मामले में दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है। केवल पानी के मामले में सरकार ने स्वीकार किया है कि दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि केवल पानी की ही बात नहीं है, दक्षिणी हरियाणा के साथ हर क्षेत्र में भेदभाव हुआ है। जो भी मुख्य मंत्री बने वे सभी चीजें अपने क्षेत्रों में ले गए। सबसे पहले तो हमारे हिस्से का पानी हमें अभी तक नहीं मिला। ये लोग भी अभी बोल रहे थे और कांग्रेस पार्टी के लोग भी बोल रहे थे लेकिन किसी ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि दक्षिणी हरियाणा का कितना पानी दूसरे क्षेत्रों में है। स्पष्ट रूप में दक्षिणी हरियाणा का महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, गुड़गांव, अहीरवाल बैल्ट का कितना पानी दूसरे क्षेत्रों में है और कितने साल से है इस तरफ किसी ने सदन का ध्यान आकृष्ट नहीं किया। जो भी मुख्य मन्त्री

बना किसी भी चीफ मिनिस्टर ने इस बारे में कुछ काम नहीं किया। हमारे इलाके में 1400 फीट पानी नीचे चला गया है और 150 गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है। आज भी हमारे पास पीने के पानी का कोई इन्तजाम नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि नई सरकार बनी है वह पानी देगी एस०वाई०एल० बनेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूं और पिछले 10 सालों से हम लोग सड़कों पर लाठी भी खा रहे हैं और जेल में भी जा रहे हैं। सभी सरकारों में हमने जेल काटी है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय हालत यह है कि हमारे दक्षिणी हरियाणा में पीने का पानी नहीं है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे और एस०वाई०एल० के ऊपर कहा गया है कि कुछ किया जाएगा। एस०वाई०एल०-एस०वाई०एल० सुनते हुए बहुत साल हो गए और इस पर बहुत राजनीति भी हो गई है। पंजाब के लोग भी एस०वाई०एल०पर राजनीति कर रहे हैं और हरियाणा की राजनीतिक पार्टियां भी एस०वाई०एल०पर राजनीति कर रही हैं। आज एक डैड लाईन खींच देनी चाहिए कि एस०वाई०एल०कब बनेगी, किस दिन बनेगी ? अगर नहीं बनेगी तो सदन में जितने भी मैम्बर्ज है क्या सभी लोग एस०वाई०एल० के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं ? जैसे पंजाब के लोगों ने फैसला कर दिया और पंजाब की सरकार ने पंजाब विधान सभा में प्रस्ताव पारित कर दिया और यह कह दिया कि हम हरियाणा को एक बून्द पानी की नहीं देंगे और ना किसी समझौते को मानेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि सदन में जो पहले सदस्य थे उन्होंने इस बात के लिए क्या कोई कार्यवाही की है ? हम तो नये सदस्य चुन कर आये हैं। प्यासे तो हम मर रहे हैं और इलाका भी हमारा बर्बाद हो रहा है जबकि पानी के ऊपर सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दक्षिणी हरियाणा में पानी तो है नहीं। भगवान ने कुछ पहाड़ दिये थे कुछ नदियां दी थीं जो कि सूख गई, उन पर भी पिछली सरकार की ऐसी नजर पड़ी की पहाड़ों की भी लीज उठा दी। वहां पर इनका एक ही मालिक है मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की सारी लीज, सारे पहाड़ और क्रैशर रोड़ी की ब्लैक मार्कीटिंग हो रही है। इन चीजों पर कई तरह के टैक्स नाजायज लगे हुए हैं अभी भी कुछ लोग वहां पर इल्लीगल बैठे हुए हैं। आपकी सरकार तो बन गई है। आप लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन गई है इस बारे में काफी लोगों ने भाषण दिये और कहा कि पिछली सरकार ने लोगों को तंग किया। अध्यक्ष महोदय, वहां पर अभी भी वही लोग कमा रहे हैं और वही लोग फायदा उठा रहे हैं । मैं माननीय मुख्यमन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त प्रभाव से इन लीजों को कैंसिल किया जाए और नये लोगों को इसका फायदा उठाने दिया जाए। साथ ही सरकार से निवेदन है कि उन लोगों पर अंकुश लगाया जाए। इसके अलावा स्पीकर सर, अस्पतालों में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अटेली मण्डी में एक सिविल अस्पताल है और हरियाणा में 10 वर्षों से कांग्रेस, इनैलो और एच०वी०पी० की सरकारों ने राज किया है लेकिन उस अस्पताल में एक्स-रे मशीन नहीं है। वहां पर एक एक्स-रे मशीन आई थी लेकिन आज तक उस बारे में कुछ नहीं पता है कि वह कहां पर है। मैं पिछली सरकार के वक्त में उस अस्पताल में गया था और वहां स्टाफ से पूछा था कि हमारे अस्तपाल की एक्स-रे मशीन कहां पर है तो मुझे जवाब दिया गया कि वह खराब हो गई है रिपेयर के लिए गई हुई है। उसके बाद मैं दोबारा से अस्पताल के सी०एम०ओ० के पास गया और उनसे भी पूछा कि हमारे अस्पताल की एक्स-रे मशीन कहां पर है तो मुझे जवाब दिया गया कि वह खराब हो गई है और रिपेयर के लिए गई हुई है। उस वक्त मैं एम०एल०ए० नहीं था लेकिन स्पीकर सर, उस एक्स-रे मशीन का आज तक पता ही नहीं है कि वह कहां पर है।

Mr. Speaker : Please wind up. (Interruptions) Please have patience.

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, इसके बाद मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा कि हरियाणा में हमारे महेन्द्रगढ़ जिले के सबसे ज्यादा लोग समय पर बिजली का बिल देते हैं। मुख्यमंत्री जी अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो अपने यहां पर उपस्थित अधिकारियों से जानकारी ले सकते हैं। इस सबके बावजूद हमारे महेन्द्रगढ़ जिले में सारे हरियाणा से सबसे कम बिजली दी जाती है और सबसे ज्यादा जले हुए ट्रांसफार्मर्ज भी आपको हमारे महेन्द्रगढ़ जिले में ही मिलेंगे। वहां पर न बिजली है, न सही ट्रांसफार्मर्ज हैं और न ही नहरी पानी है। स्पीकर सर, जब वहां पर नहरी पानी नहीं है तो सरकार को चाहिए कि वहां पर बिजली को सब्सीडाईज्ड दामों पर दिया जाना चाहिए।

Mr. Speaker : Thank you, Please wind up, Mr. Yadav.

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, मैं कुछ मामलों के बारे में और कहना चाहता हूं। स्पीकर सर, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे इलाके के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। जहां के मुख्यमंत्री बनते हैं वहीं पर यूनिवर्सिटी खोल दी जाती है। अभी पिछली सरकार के वक्त में ओम प्रकाश चौटाला जी ने चौधरी देवी लाल जी के नाम से यूनिवर्सिटी अपने एरिया सिरसा में खोल दी। हम तो यह कहते हैं कि हमें नाम से कोई प्रोब्लम नहीं है आप उस यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी देवी लाल ही रख लेते लेकिन उसको हमारे इलाके में खोल देते ताकि वहां की जनता का भी भला हो जाता। स्पीकर सर, हमारा इलाका सैनिकों का इलाका है और कारगिल युद्ध में हमारे इलाके से 133 फौजी शहीद हुए थे लेकिन वहां पर फौजियों के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं न ही वहां पर कोई सैनिक स्कूल है, न कोई सैनिक अस्पताल है और न ही दूसरी कोई सुविधाएं हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह सरकार दक्षिणी हरियाणा की तरफ भी गौर करें। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Now, Sh. Dharmbir Singh will speak.

श्री धर्मबीर सिंह (बादड़ा) : स्पीकर सर, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन में पढ़ा था और सुरजेवाला जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है मैं उस पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्पीकर सर, इस सरकार को बने अभी 16-17 दिन ही हुए हैं। हमारी आदरणीय नेता सोनिया जी ने हरियाणा में एक बहुत ही ईमानदार नेता को मुख्यमंत्री बनाया है। पिछली सरकार के वक्त में हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार में बिहार और यू०पी० से भी उपर आ गया था लेकिन इस सरकार ने इन 16-17 दिनों में जो निर्णय लिए हैं उससे प्रदेश के लोगों में विश्वास जागा है कि हरियाणा में जितनी बीमारियां लग गई थीं वह अब दूर हो जाएंगी। हुड्डा साहब, हमारे नेता हैं। इन 16 दिनों में उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं थाहैं उन निर्णयों में आई०पी०एस० और आई०ए०एस० आफिसर्ज की बदलियां की है दूसरे अच्छे निर्णय लिए हैं उससे हरियाणा के लोगों में विश्वास जागा है कि हरियाणा में जो भ्रष्टाचार फैल गया था, अब उस पर अंकुश लग जाएगा। स्पीकर सर, सोनिया जी की अध्यक्षता में हरियाणा के इलैक्शन मैनीफैस्टो में चुनाव से पहले जो घोषणाएं की थीं, उनको 100 प्रतिशत लागू करने की कोशिश की गई है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अगर सबसे ज्यादा ध्यान किसी बात पर दिया है तो वह यह है कि उन्होंने अनुभवी आदमियों को और ईमानदार आदमियों को अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। अध्यक्ष महोदय, 70 प्रतिशत से ज्यादा हमारे प्रदेश की जनता कृषि पर निर्भर है। आज का दक्षिणी हरियाणा पिछले कई सालों से इस बात के लिए संघर्ष कर रहा था कि हमें भी बाकी हरियाणा के

बराबर पानी दिया जाए क्योंकि हरियाणा के उस साईड में पानी नहीं था। अध्यक्ष महोदय, आज भी सौ से भी ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है और जहां पर वाटर लेवल भी बहुत कम हो चुका है। पहले हमें यह कहकर बहकाया जाता था कि जब एस०वाई०एल० कैनाल बन जाएगी तो रावी ब्यास का पानी आपको मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता तो यह चाहती थी कि जो पानी सतलुज और ब्यास का अभी तक हमें मिलता है उसमें से तो उनको पूरा हिस्सा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का कुछ इलाका तो ऐसा है जहां दस मिनट में एक किल्ला भर जाता है और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर एक महीने तक पानी नहीं आता था और अगर पानी आता भी था तो यह कह दिया जाता था कि आपको केवल पीने का पानी ही मिलेगा खेती का नहीं। मौजूदा सरकार ने बनते ही नहरी पानी का बराबर समान बंटवारा करने का फैसला लिया है, यह एक स्वागत योग्य बात है। सरकार के इस फैसले का स्वागत सारी हरियाणा प्रदेश की जनता ने ही नहीं बल्कि इस हाउस के एम०एल०एज० ने भी किया है। अभी हमारे सामने बैठे विधायक डा० सीताराम जी ने भी यह कहने की कोशिश की कि उनकी सरकार बनने से पहले भी इस बारे में गलत काम हो रहे थे इसलिए अगर पानी का बंटवारा समान रूप से किया जाता है तो वे भी इसमें शामिल हैं और यह बंटवारा ठीक किया ही जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सारा हाउस इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी है। गवर्नर महोदय ने भी अपने अभिभाषण में यह बात स्पष्ट कर दी है कि प्रदेश के पानी का बंटवारा समान रूप से होगा। अध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या के बाद एक समस्या बिजली की भी है। पिछली सरकार ने स्लैब प्रणाली खत्म की थी और यह सिस्टम करने की कोशिश की कि जहां पर पानी 25 फुट गहरा है और जहां पर 6 इंच की पानी की निकासी थी वहां पर भी वही रेट लिए जाएंगे और जहां पर पानी चार सौ फुट गहरा है और बीस होर्स पावर की मोटर लगाने के बाद भी केवल दो इंच ही पानी निकलता है वहां पर भी वही रेट लिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी स्लैब प्रणाली जरूर शुरू करें ताकि पैसा बराबर देकर बराबर पानी निकाला जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सरकार ने आते ही यह भी निर्णय लिया कि कुदरत की मार पड़ने पर जैसे ओलावृष्टि आदि होने पर उनकी फसलों के खराब होने की स्थिति में पचास परसैंट ज्यादा मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो लोग ठेके पर जमीन लेकर खेती करते हैं तो मैं चाहूंगा कि इस तरह का पैसा जमीन मालिक के बजाए खेती करने वाले को मिलना चाहिए। जहां पानी का समान बंटवारा है वहां पर हर माईनर और हर नहर पूरे सात दिन तक चलनी चाहिए। जहां पर पम्प हाउसिज खराब हैं उनको भी सुधारा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज से बीस-बाईस साल पहले शायद उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, के वक्त में स्प्रिंकलर सैट्स खरीदे गये थे लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनमें से तकरीबन पचास परसैंट स्प्रिंकलर सैट्स पिछली सरकार ने बगैर यूज किए थोड़े पैसों में कहीं बेच दिये या ट्रांसफर कर दिये। मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्प्रिंकलर सैट्स खरीदकर महेन्द्रगढ और भिवानी के इलाकों में चालू किये जाएं ताकि कम पैसों से ज्यादा सिंचाई हो सके। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितनी बड़ी बड़ी नहरें हैं खासकर जितने फीडर हैं उनमें डायरैक्ट आउटलैट लगे हुए हैं। मेरा सिंचाई मंत्री से अनुरोध है कि किसी भी क्षेत्र में अगर इस तरह के डायरैक्ट आउटलैट फीडर में लगे हुए हैं तो वे सभी आउटलैट फीडर से उखाड़े जाएं। इसी प्रकार से कृषि के मामले में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। सरसों की फसल आ चुकी है। भारत सरकार ने इसके रेट फिक्स कर रखे हैं लेकिन इसके जो रेट तय किये गये हैं उस रेट पर सरकारी एजैंसीज सरसों की खरीद नहीं कर रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि

[श्री धर्मबीर सिंह]

पिछली सरकारों की तरह बिचौलिए अपने आदमियों की सरसों खरीद लें और दूसरे आदमियों की न खरीदें। मेरी मांग है कि सरसों की खरीद के सिस्टम को भी सुधारा जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने माइनिंग के बारे में एक मिनट में फैसला लिया कि अवैध नाके बंद हों। सारे प्रदेश में पिछली सरकार ने जो गलत काम किए थे अब वह बर्दाश्त नहीं होंगे। इस बारे में मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश की जनता का पैसा गलत तरीके से वसूला है चाहे वह टैक्स के रूप में वसूला हो, चाहे किसी भी तरीके से वसूला हो । पिछले पांच साल में इन्होंने माइनिंग के ऊपर बैठकर जो पैसा वसूला है उसकी इंक्वायरी किसी भी उच्चाधिकारी से कराकर जिसने जितना पैसा माइनिंग से वसूला है उसकी इंक्वायरी करवाकर पैसा जरूर वापस दिलवाया जाए। इसी प्रकार से एजूकेशन के मामले में मैं मानता हूं कि हर जगह सरकार अपने कालेज नहीं चला सकती लेकिन प्राइवेट कालेज खोलने के लिए हमारे पास बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं जो प्रदेश से बाहर गए हुए हैं उनसे भी लाइजनिंग की जा सकती है उनसे कहकर प्राइवेट कालेज चालू करवाए जाएं। पब्लिक ने मिलकर बाढड़ा में कालेज बनवाया है उसकी भी स्वीकृति दें जहां जहां स्टाफ की कमी है चाहे तोशाम में है या भिवानी का आदर्श कालेज है इनकी बिल्डिंग बनी हुई हैं। फाइनैंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं पिछली सरकार ऑब्जैक्शन लगा देती थी कि फंड्स की कमी है। एक-एक कालेज में 20-20 लैक्चरर थोड़े से पैसे पर रखे जाते हैं लैक्चर्स की स्वीकृति सरकार दे ताकि वहां के बच्चों को पढ़ने की सहूलियत हो जाए। (विघ्न) मैं ज्यादा समय लेते हुए आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सुरजेवाला जी ने गवर्नर साहब के ऐड्रस को पास करवाने के लिए सभी चीजों के बारे में पूरी रोशनी डालने की कोशिश की है। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं कुछ ही बातें कहना चाहूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से आने वाले पांच साल की अपनी नीतियों को आपके सामने रखा है सदन के सामने रखा है और सदन के माध्यम से जनता के सामने रखा है । अध्यक्ष महोदय, भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन यानी ये चीजें सुनने वाले हर व्यक्ति को बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन स्पीकर सर, यह बहुत ही कठिन काम है। बड़ा भारी चैलैंजिंग टास्क है। हमारी सरकार की जो गशीनरी है उसको पिछले पांच सालों में न सिर्फ जंग लगा दिया गया बल्कि इसको गला दिया है। आज भी ऐसे उच्चाधिकारी जो भ्रष्टाचार में तथा क्राइम में टोटली इन्वौल्व थे, ऐसे अधिकारियों का अभी भी फील्ड में कोई न कोई रोल रहेगा, इसका मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे ऊपर बेशुमार नाजायज मुकदमें बनाए गए, कत्ल के मुकदमे इतनी सरलता से बनाए, उन उच्चाधिकारियों से जब तक आप सवाल जवाब नहीं करेंगे और जब तक उनको सजा नहीं देंगे, जब तक ऐसा वातावरण नहीं बनाएंगे कि किसी उच्चाधिकारी को इस प्रकार का खिलवाड़ करने की मजाल नहीं होगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक ये खिलवाड़ करने से बाज नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे अधिकारी रहे हैं कि दर्खास्त एस०पी० को लिखी हुई है और 15.00 बजे उसके ऊपर आदेश डी०सी० दे रहे हैं। 302 के मुकदमें बनाये और कोर्टस के फैसले में यह कहा गया Prosecution should be ashamed of framing such charges where there is no evidence.

And we have suffered for 3 years. In my case I was booked under a case under Section 302 in which there was no evidence. And I was going to the Court up

and down for three long years. Finally, the prosecution could not produce any evidence against me and we were acquitted honourably. स्पीकर सर, पहले ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने लोगों के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया हो बल्कि ऐसे भी अधिकारी रहे हैं जिन्होंने जनता के प्रतिनिधियों से भी उनकी शान में गुस्ताखी की और उन्हें फिजीकली असाल्ट किया। मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर अर्ज है कि ऐसे व्यक्तियों को सजा जरूर दी जाये। यह संभव है कि इस बारे में काफी सिफारिशें भी आयेगीं और जातिवाद व रिश्तेदारियों की बात भी आयेगी। अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसे अधिकारियों को बख्शा जाता है तो वह जनता के साथ खिलवाड़ होगा। पिछले शासन में ऐसे-ऐसे पुलिस अधिकारी भी रहे हैं जिन्होंने लोगों को अगवा करवाया। एक मुलजिम जो बहुत अर्से बाद पकड़ा गया था। वहीं घूमता रहा और सुनते हैं कि वह काफी समय तक चौटाला में रहा और काफी अर्से बाद आखिरकार पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसने प्रैस में यह स्टेटमेंट दी कि मैंने एक सेठ के लड़के को 10 लाख रुपये की फिरोती के लिए पकड़ा था और उस काम में मेरा सहयोग कैथल के एस०एस०पी०, एक इन्सपैक्टर और दूसरे अधिकारियों ने दिया था। उसके बाद उस अपराधी को चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने इनाम में मैडल भी दिया। ऐसे भी व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने किसानों को भूना है और जो अब भी खुले आम घूम रहे हैं। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार में ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने किसानों को परेशान किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम किसानों और मजदूरों की लड़ाई उनकी अध्यक्षता में लड़ते थे तब इन्होंने किसानों को यह वचन दिया था कि अगर उनकी सरकार आयेगी तो वे ऐसे अधिकारियों को माफ नहीं करेंगे। लेकिन आज वही अधिकारी अगर महत्वपूर्ण जगहों पर लगे रहेगें तो वे सरकार में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बलड़ी गांव में एक नौजवान का कत्ल किया था और बाद में उसको मुठभेड़ दिखाया था।

स्पीकर सर, बहुत ही अच्छी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है कि वे भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनते ही कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए काफी एक्सरसाईज की है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति सरकार के अन्दर अब भी मौजूद हैं उच्च प्रणाली में, ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं जो कांग्रेस की पिछली सरकार के समय में भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, गबन के केस में सस्पैंड थे, ऐसे-ऐसे आई०ए०एस० अधिकारी जो पांच साल तक सस्पैंड रहे और जैसे ही सरकार का परिवर्तन हुआ जिन्होंने भ्रष्टाचार की मिसाल कायम की हुई थी वे अधिकारी भी अच्छी पोस्टिंग पाने में जैसे एच०एस०आई०डी०सी० वगैरह में और दूसरी जगह पर महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने में कामयाब हुए। जिन लोगों ने उनको भ्रष्टाचार के मामले में पकड़वाया था उनसे बदला लेने में वे कामयाब हुए। इन सारी चीजों का आप जायजा लें और मुझे आशा और विश्वास है कि आपने उपयुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का जो लोगों से वायदा किया था, उसे आप पूरा करेंगे।

इस अभिभाषण में खेती के बारे में चिन्ताजनक बात का जिक्र करते हुए बहुत से सुझाव आये हैं। यहां पर क्रोप डाइवर्सिफिकेशन की बात भी की गई है श्री सुरेन्द्र सिंह जी, जो हमारे बीच बैठे हुए हैं उन्होंने क्रोप डाइवर्सिफिकेशन की बात की है। इस बारे में हम बहुत ही मुद्दत से सुनते आ रहे हैं कि क्रोप डाइवर्सिफिकेशन हो। तरह-तरह के बड़े-बड़े प्रतिनिधि मण्डल इस मामले में विदेशों में भी गये। ग्रीन हाउस की प्रणाली बनाई गई, ड्रिप इरीगेशन की योजना बनाई गई, स्प्रिंकलर सैट्स की योजना बनाई गई लेकिन अब तक इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अध्यक्ष

[श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान]

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पिछले पांच सालों में किसानों का मण्डियों में शोषण हुआ है और उसकी एवज में पिछले मुख्यमंत्री और उनके ***** हासिल की है। ****के माध्यम से किसान की जीरी 100 रुपये प्रति क्विंटल कम बिकी थी क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करते थे और जेलों में जाते थे और सरकार का ध्यान आकर्षित करते थे। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से वह अन्धी और बहरी सरकार और एक भ्रष्ट सरकार होने की वजह से उसने किसानों का खुन निचोड़ा था। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे ताकि भविष्य में किसानों का शोषण न हो। आज एम०एस०पी० के बारे में अखबार में एक खबर थी कि सरसों की फसल मिनिमम स्पोर्ट प्राइज से कम बिक रही है, यह बात आपके नोटिस में आ गई होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इन सारी बातों पर ध्यान देगी। हम यह बात भी बार-बार करते हैं और सुरजेवाला जी ने भी कही है कि कम सूद पर किसान को ऋण मिलना चाहिए, हमारी यह मांग सदा से ही रही है। किसान का काम केवल ऋण लेने से चलने वाला नहीं है। आज हमारी भूमि की जोत बहुत छोटी हो गई है जिसकी वजह से आज कृषि करना न सिर्फ अनइक्नोमिकल है बल्कि उसके ऊपर निर्भर रहने से तो अच्छा मजदूरी कर लेना है। हमारी प्रति एकड़ आमदन क्या हो इसका निर्णय दिल्ली की सरकार करती है पिछले 5 सालों के संघर्ष का जो जीवन हमने बिताया है उसमें हम बार-2 एक चीज के ऊपर जोर देते रहे कि किसान को अच्छी मिनियम स्पोर्ट प्राइज हम दिलवाएंगें। आज सौभाग्य से आप लोगों के लिए यहां भी कांग्रेस की सरकार है और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार है। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हुए गेहूं, जीरी, कपास, गन्ने और अन्य सभी फसलों का किसान को अच्छा मूल्य उपलब्ध करवाने की कोशिश करें। ऋण लेना सुविधा तो है लेकिन यह लोन लेना कोई मीन्स नहीं है। ऋण लेना जिंदगी बिताने के लिए कुछ हद तक ही उचित है। दिल्ली में बातें होती हैं कि हमने ऋण देने की सीमा को इतना बढ़ा दिया, सूद को कम करने की मांग तो जायज है लेकिन ऋण की सीमा रेखा को ज्यादा बढ़ाना मैं समझता हूं कि बोझ को बढ़ाना है। अध्यक्ष महोदय, लोगों को काम देने के हमें नए तरीके ढूंढने होंगे और गांव के अंदर कोटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना होगा। कोटेज इंडस्ट्रीज को बढावा देने के लिए मार्किटिंग की भी बड़ी आवश्यकता है। एक छोटा किसान, गरीब आदमी, एक दलित, एक गांव का कुम्हार अपनी बनी चीजों को मार्किट में कहीं बेच नहीं सकता, इसलिये उनके लिए सरकार को कहीं न कहीं मार्किटिंग प्रणाली को बनाना होगा। जब कांग्रेस की पिछली सरकार थी, तब इस बारे में एक बड़ी भारी योजना कुण्डली में बनाई गई थी उस योजना के अन्दर डायवर्सीफिकेशन का एक नजरिया था, डायवर्सीफिकेशन के लिए वहां फूलों के लिए, तिलहन के लिए और दूसरी सारी चीजों की मार्किटिंग के लिए प्रावधान किया गया था लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है बड़ी सरलता के साथ उस सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर को पिछली सरकार ने HSIDC और दूसरी संस्थाओं को दे दिया।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, अब आप जल्दी वाईड अप करें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, आपने औरों को 15-15 मिन्ट बोलने का समय दिया है मुझे तो बोलते हुए अभी 5 मिनट ही हुए हैं, मेरी तो अभी लय ही बनी है और आप मुझे वाइंड अप करने के लिए कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं यूनीवर्सिटीज की बाबत कुछ

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से एक्सपंज कर दिए गए।

कहना चाहूंगा और सुरजेवाला जी ने भी इसके बारे में कहा था। यूनीवर्सिटी में कार्य करने वाले एक क्लर्क को वहां का सभापति बनाया गया और बाद में उसे वाइस चांसलर बनाया गया यह बड़े दुख की बात है। इस प्रकार के पदों पर कार्य करने के लिए तो बड़े विशेषज्ञ होने चाहिएं। 5 साल से किसी यूनिवर्सिटी ने किसी क्राप का नया बीज नहीं निकाला यह बड़े अफसोस की बात है । हमारी हिसार यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं लेकिन वह यूनिवर्सिटी ***आज बनकर रह गई है। सैंकड़ों आदमी हिसार यूनिवर्सिटी और कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बाहर से आते हैं ऐसा सुनने में और देखने में आया है कि लोग वहां पर जबरदस्ती खाना खा करके चले जाते हैं। मुझे यकीन है सरकार के परिवर्तन के बाद यहां के वातावरण में जरूर बदलाव आया है लेकिन इस बदलाव को बनाए रखने के लिए सख्त निगाहें रखनी पड़ेंगी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को स्वच्छ वातावरण देने के लिए पोल्यूशन बोर्ड बनाया गया है और इस बोर्ड की कार्यप्रणाली को मैं 20-30 सालों से देखता आ रहा हूं। इंडस्ट्रीज वालों को एक बहुत छोटी सी रकम अपना पोल्यूशन यंत्र लगाने के लिए पोल्यूशन बोर्ड को देनी पड़ती थी। लेकिन पिछली सरकार ने 5 सालों में इस पोल्यूशन बोर्ड को प्रदेश से पोल्यूशन दूर करने की बजाय अपने सियासी विरोधियों को काटने के लिए एक यंत्र बनाया था। मेरी अपनी एक छोटी सी पेपर मिल है यह मिल पोल्यूशन के सारे पैरामीटर्स पूरे करती थी लेकिन फिर भी 300 सिपाहियों को ऊपर चढ़ाकर उसके अन्दर ताले लगवा दिए गए और कहा गया कि इससे दूषित पानी जाता है। दुर्भाग्य से 300-400 परिवार जो इस मिल से अपनी रोजी रोटी कमाते थे वे परिवार अपनी रोजी रोटी कमाने से वंचित हो गए। मैं चाहूंगा कि इस पोल्यूशन बोर्ड का सही इस्तेमाल किया जाए। यही नहीं हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए हमारे अरोड़ा साहब ने जो ब्यान दिया है वह स्वागत योग्य है। हमें खुशी है कि इन्होंने बाहर के उद्योगपतियों को हरियाणा में उद्योग लगाने का न्यौता दिया है। अब इस सरकार के बनने के बाद बाहर के उद्योगपति प्रदेश में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आने को तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, हम दिल्ली के तीन तरफ हैं और उद्योग लगाने की यहां सुविधा भी है । मैं अरोड़ा साहब से कहना चाहूंगा कि केवल न्यौता देने से काम नहीं चलेगा बल्कि आप सभी इण्डस्ट्रियलिस्टस की मीटिंग बुलायें और उनके अंदर विश्वास कायम करें। यह जो लैंड यूज का दुरूपयोग होता रहा है इसको भी सस्ता करिये। उद्योगपति आम किसानों की लैंड तो तभी खरीदेंगे जब लैंड यूज का पैसा आप कम लगायेंगे तभी देहात में इण्डस्ट्री आयेगी वरना तो इण्डस्ट्री इण्डस्ट्रियल स्टेट से बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम यह चाहेंगे कि आप गांवों में, बैकवर्ड इलाकों में इण्डस्ट्री लगाने की सुविधाएं दें और लैंड यूज का जो जुर्माना है, जो उसका खर्चा है वह कम से कम हो। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे बहुत बड़े उद्योगपति जिंदल साहब बिजली मंत्री बने हुए हैं। इनका बिजली उत्पादन का अपना बहुत बड़ा कारखाना है और मुझे मालूम है कि इनको बिजली उत्पादन का बहुत अनुभव है। ये अपने कारखाने में बहुत योगदान देते हैं। इसमें मुश्किल यह है कि सरकार की अवधि पांच साल है और बिजली उत्पादन का प्लांट लगने में 8-10 साल का समय लगता है। छोटी और बड़ी योजनाओं में जब तक संतुलन नहीं होगा, तब तक काम चलने वाला नहीं । जैनरेटिंग सैट्स पर, कैपेटिंग पावर पर और दूसरी चीजों पर जब तक सरकार सरलता से सबसिडी नहीं देगी तब तक यह जो बिजली की कमी है यह दूर नहीं होगी। ये सुविधाएं किसानों को भी दी जानी चाहिएं ताकि किसान भी अपने छोटे-छोटे जैनरेटिंग सैट्स लगा सकें और इण्डस्ट्रीज अपने जैनरेटिंग सैट्स अलग से लगा सकें। मुझे मालूम है कि इण्डस्ट्रीज के लिए लोन लेने के लिए लोग

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से एक्सपंज कर दिए गए।

[श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान]

दस-दस, बारह-बारह साल से लाईन में लगे होते हैं फिर भी उनको लोन आसानी से नहीं मिलता । यदि काफी समय के बाद दो-दो चार-चार लाख रुपये मिलते भी हैं तो इसके लिए भी उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। लोन लेने वालों की एप्लीकेशन पर इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए दो-दो, चार-चार लाख रुपये भी लोन के नहीं मिलते। रिश्वत भी देनी पड़ती है फिर आखिर में लाईन फेर दी जाती है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं पैसा नहीं दिया जायेगा। पिछली सरकार के समय में ऐसा मजाक उद्योगपतियों के साथ होता था। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी व्यवस्था को हमें बदलना होगा। स्पीकर सर, गरीब आदमियों को पैंशन देने की कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। पिछली सरकार के समय में हरिजन, बाल्मिकि, दलित समाज पिछड़े वर्ग और गरीब आदमी पैंशन से वंचित रहे हैं। मुझे यह पर्सनल नॉलेज है कि जैसे कैथल जिले में 18 हजार नये पैंशन के केसिज बने, ऊपर से आदेश आया कि इनको 9 हजार रखो, उसके बाद फिर आदेश आया कि 4 हजार रखो और दुर्भाग्य से उन 4 हजार में भी गरीब आदमियों को पैंशन नहीं मिली। जो मलंग थे ढींग थे वे पैंशन ले गये। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि पैंशन का सर्वे दोबारा से करवाया जाये और जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको अधिकार दिया जाये कि वे अपने अपने क्षेत्र के गरीब आदमियों को, बुजर्गों को, माताओं को, विधवाओं को पैंशन दिलवाने में सक्षम रहें। इसी प्रकार से गुलाबी और पीले कार्डों की भी बड़ी भारी समस्या है। हम प्रचार के दौरान, संघर्ष के दौरान कहते रहे हैं कि पिछली सरकार में बहुत भेदभाव हुए हैं और मेरा ख्याल है कि मुख्यमंत्री जी भी इस बात से अवगत हैं इसलिए इस सर्वे को भी दोबारा से करवाया जाये तथा सर्वे करवाने से पहले गरीबी की लाईन को भी ऊपर करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो गरीब लोग हैं वे और गरीबी में धंसते चले जा रहे हैं, लोगों को हमें सुविधाएं देनी ही होंगी। एक तरफ किसानों को उनके जिन्स के दाम देने होंगे दूसरी तरफ हर जाति के गरीब लोगों को विशेषकर दलितों को, बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को अन्य सुविधाएं देनी होंगी । हमें उनको सस्ती चीनी और अनाज की सुविधा देनी होगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे भी सरकार में रहने का मौका मिला । मेरे पास I.T.I. विभाग था, । I.T.I. विभाग में मैंने बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन पैदा किया था। मैंने I.T.I. विभाग के अंदर उन सब इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज को इन्वोल्व किया था, जो हमारे बच्चों को बाद में नौकरियां देती थी। लेकिन बाद की सरकारों ने मेरी वह प्रथा बदल दी। मैं फूलचन्द मुलाना जी से प्रार्थना करूंगा कि जितनी इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज हरियाणा में हैं उन सब में एक-एक, दो-दो I.T.Is.को इन्वोल्व करें। जैसे फरीदाबाद में, करनाल में, गुड़गांव में और यमुनानगर आदि कई जगहों पर इस तरह की इण्डस्ट्रीज हैं। करनाल में तो हमारा लिबर्टी ग्रुप है। यहां पर विशेषकर हमारे दलितों के लिए एक नई प्रणाली इस प्रकार की बन सकती है। जिस के तहत उन्हें रोजगार मिल सके। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ओल्ड ऐज होमज की बात करना चाहूंगा। हमारे गांवों में दो-दो कमरों के मकान ओल्ड ऐज होमज के नाम पर बना तो रखे हैं लेकिन उनमें सूअर पलते हैं । वहां कोई ओल्ड ऐज होम का प्रावधान नहीं है। मैं चाहूंगा कि ओल्ड ऐज होमज की जिम्मेवारी सोशल संस्थाओं को दी जानी चाहिए और सरकार उन संस्थाओं को वित्तीय सहायता देकर मदद करे। हमारे यहां बहुत से गुरुकुल और दूसरी संस्थाएं हैं जो उन्हें लेना चाहती हैं। इन सभी बातों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए इसका अनुमोदन करता हूं और सरकार को बहुत-बहुत मुबारकवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री शांदीलाल बतरा (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हरियाणा की जनता की दूरदर्शिता पर, उसकी पोल्टिकल मेच्योरिटी पर और उसके पिछले इलैक्शन में लिए गए निर्णय के लिए शत-शत नमस्कार करके उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से आंतकवादी और भ्रष्टाचारी सरकार को चलता किया । लोगों ने अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए जो सपने संजाये थे उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कांग्रेस की सरकार चुनी है। मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी एक निष्ठावान, ईमानदार और एक सच्चे सेवक को इस प्रदेश का मुखिया बना कर हमें और इस विधान सभा में उनके नेतृत्व में काम करने का एक मौका दिया है। इसके लिए मैं उनका भी आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार केवल भ्रष्टाचार से चली। यह भ्रष्टाचार सिर्फ जनता में ही नहीं था बल्कि सरकार में भी था। जब पिछली बार बजट पेश किया गया तो उस वक्त सिर्फ 1471 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था जबकि बाद में जा कर वह घाटा 2923 करोड़ पर खत्म हुआ। यह पिछली सरकार 1999 में आई थी और 2005 तक रही। जब उस सरकार ने सत्ता संभाली थी तो उस वक्त 12249 करोड़ रुपये के लोन सरकार पर थे जो उनके समय में बढ़कर 22194 करोड़ रुपये हो गए यानि वे इतने रुपये लोन के छोड़ कर गए हैं। इस लोन पर जो इन्ट्रैस्ट लगता है उसमें भी 56 परसेंट की वृद्धि हो गई। पिछली सरकार ने 2002-03 में 172 करोड़ 59 लाख रुपये ऐसे खर्च किए जिनकी पहले कोई मन्जूरी नहीं ली गई और न ही उस खर्चे का कोई प्रावधान था। वह सरकार सरकारी बजट को इस प्रकार खर्च करती थी और सरकारी कोष को इस तरह लूटती थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा की जनता ने उसको चलता किया इसके लिए मैं हरियाणा की जनता को बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं। उस वक्त की सरकार ने जब सत्ता संभाली तो एरियर्ज आफ रवैन्यू 312 करोड़ रुपये के थे और वे जाते हुए एरियर्ज आफ रवैन्यू के 851 करोड़ रुपये छोड़ करके गए हैं। ऐसी सरकार के मुखिया ऐसी दीमागी बीमारी से ग्रस्त थे जिसका कोई हिसाब नहीं है। वे कहते थे कि जब तक मैं जिन्दा रहूंगा इसी कुर्सी पर बैठा रहूंगा। मेरी आखरी सांस तक मेरी सरकार चलेगी। सरकार का डर इतना था कि कोई बोलता नहीं था। उस वक्त की सरकार का सिवाये आंतक और भ्रष्टाचार फैलाने के अलावा और कोई कोई काम नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा की कि हम अत्याचार और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार प्रदेश को देंगे। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई है। कहते हैं कि "Morning shows the day". इस सरकार की उम्र आज केवल 17 दिनों की है। इन 17 दिनों में इस सरकार ने जितने अच्छे फैसले लिए हैं वे आपके सामने हैं और जो फैसले लिए गए हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा नहीं तो आप कहेंगे कि समय समाप्त हो गया। मुझे इसमें एक बात नजर आती है कि इस मौजूदा सरकार का हर फैसला जनता ने सराहा है और अब सभी वर्ग के लोग खुश हैं। चाहे सरकारी कर्मधारी हैं या व्यापारी हैं सभी ने यही कहा है कि यह नई सरकार जिस ढंग से चल रही है वह बहुत सराहनीय है। यह हमारी सरकार चलते-चलते उस दिशा में और उस मंजिल पर पहुंचेगी जिस मंजिल पर हरियाणावासियों ने अपने सपने संजो रखे हैं। चाहे वे सपने सुरक्षा के हैं और चाहे वे सपने विकास के हों सभी सपने पूरे होंगे। आज डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी आफिसर्ज आए हैं उन आफिसर्ज पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रशासन में निष्ठावान और ईमानदार छवि के जो व्यक्ति आए हैं उनसे हमें विश्वास भी है कि अब तक तो व्यक्ति आए हैं वे जनता की सेवा करने के लिए आए हैं।

[श्री शादीलाल बतरा]

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं शिक्षा की नीति पर अपनी बात कहना चाहता हूं। पिछली सरकार की शिक्षा की नीति क्या थी यह सभी को पता है। उनकी सरकार में शिक्षा इतनी महंगी हो गई थी जिनका कोई हिसाब नहीं है। उनके समय में किसी गरीब का बेटा डाक्टर बनने के लिए या इन्जीनियर बनने के लिए सोच नहीं सकता था चाहे उसमें कितने ही अच्छे गुण हों। अगर उसके बाप के पास पैसा नहीं था तो वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। जो कालेजिज हैं उनमें सरकार की तरफ से ग्रान्ट मिलती है। अगर कालेज के किसी विभाग के लैक्चरार की भगधान न करे, डैथ हो जाए तो उसके बदले उसके परिवार के दूसरे व्यक्ति को नौकरी में लेने की जो मंजूरी थी वह भी उन्होंने समाप्त कर दी। इतना ही नहीं यदि किसी लैक्चरार की रिटायरमेंट हो जाती है तो उसके बाद दूसरा लैक्चरार भी नहीं रखते थे क्योंकि वे उसका खर्चा वहन नहीं कर पाते थे। इससे नुकसान किसी और का नहीं केवल बच्चों का होता था। आज शिक्षा संस्थानों में बहुत स्थान रिक्त पड़े हैं। पहले इन रिक्त स्थानों की भर्ती करने के लिए सरकार की तरफ से मन्जूरी नहीं मिलती थी। ऐसी सरकार जो शिक्षा पर आघात करे, जो यह चाहे कि हरियाणा के बच्चे पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त न कर सकें और हरियाणा के बच्चे अपने आप को पूरा विकसित न कर सकें तो ऐसी सरकार का क्या फायदा था ? शिक्षा के बारे में अब हमारी सरकार की ऐसी सोच नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीति ऐसी नहीं है। हमारी सरकार की सोच यह है कि हमने जो शिक्षा देनी है वह सस्ती होनी चाहिए, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए और उसके द्वारा हर हाथ को रोजगार मिलना चाहिए। सरकार का पहला दायित्व यह होता है कि प्रदेश की जो जनता है उस के हर हाथ को काम मिलना चाहिए ताकि वे समाज की मुख्य धारा का अभिन्न अंग बन कर रहें और मुख्य धारा से विमुख न हों। मुख्य धारा से विमुख न होने के लिए यह जरूरी है कि उनकी आर्थिक पोजीशन ऐसी हो कि उनके परिवार की पालना ठीक से हो सके और वे लोग अपने तथा अपने परिवार की पालना ठीक तरह से कर सकें। पिछली सरकार ने क्या किया, जिन लोगों की अलग-अलग महकमों में 25-25, 30-30 साल की सर्विस थी वे डिपार्टमैंट बन्द कर दिए। एम०आई०टी०सी० का डिपार्टमैंट ठीक प्रकार से काम कर रहा था और उसमें लोगों को रोजगार भी मिला हुआ था। ऐसा नहीं था कि एम०आई०टी०सी० का कार्य खत्म हो गया था, कार्य चल रहे थे लेकिन कार्यों के चलने के बावजूद उन्होंने डिपार्टमैंट खत्म कर दिया। अगर डिपार्टमैंट को खत्म भी करना था तो एम०आई०टी०सी० के जितने भी कर्मचारी थे उनका कोई वैकल्पिक प्रावधान करना चाहिए था। किसी और डिपार्टमैंट में उन कर्मचारियों को लगाया जाना चाहिए था या उनको ऐसे साधन बना कर देने चाहिए थे जिससे वे अपना गुजारा कर सकें। एम०आई०टी०सी० के कर्मचारी हजारों की संख्या में हैं और वे आज सड़कों पर हैं । उपाध्यक्ष महोदय आप कभी भी देखें, मुझे तो ऐसे कई परिवारों को देखने का मौका मिला है। कई लोगों की 30-30 साल की नौकरी हो गई थी लेकिन अब नौकरी से निकाल देने के बाद अब उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। वे लोग अपने घरों में खाली बैठे हैं और परेशानी में आत्महत्या करने की सोचने लग गए हैं। ऐसी सरकार का क्या करें जो रोजगार देने की बजाए रोजगार छीने। आज लोग इस सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वे यह सोचते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ ऐसा कार्य करेगी जिससे हरियाणा का हर बच्चा, हर वासी खुश होगा और गर्व से कह सकेगा कि वह हरियाणावासी है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अब जमीनें बहुत थोड़ी हो गई हैं। इसलिए अब प्रदेश में इण्डस्ट्रियलाईजेशन होना चाहिए। जब इण्डस्ट्रिलाईजेशन होगा तो ऐनसिलरीज लगेंगी और उन

बच्चों को जो नौजवान हो चुके हैं, अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं, रोजगार का कोई न कोई साधन मिल जाएगा । उनको कहीं पर नौकरी मिल जाएगी जिससे वे अपना गुजारा कर सकेंगे और आने वाले बच्चों का लालन-पालन बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से कहूंगा कि यहां पर इण्डस्ट्रियलाईजेशन होना चाहिए। रोहतक में कोई बड़ी इण्डस्ट्री नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई न कोई ऐसी मदर इण्डस्ट्री वहां पर लगाई जाए जिससे वहां के बच्चों को रोजगार मिल सके। मदर इण्डस्ट्री लगने के बाद उसकी ऐनसिलरीज भी आएंगी और दूसरी चीजें भी आएंगी। उपाध्यक्ष महोदय, विकास के मामले में हमारा रोहतक भेदभाव का शिकार रहा है और आज विकास की दशा ऐसी है कि हम कह सकते हैं कि गांव के लोग भी उससे अच्छे तरीके से रहते हैं। यहां पर पानी की बड़ी भारी प्रॉब्लम है। 1966 में हरियाणा बना था। हरियाणा बनने के बाद आज 1966 से 2005 हो गया है लेकिन हमारे लोगों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि उसको पीने का पानी मिले लेकिन पानी की बहुत ही कमी है। वहां पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और जो मिल भी रहा है वह इतना गन्दा मिल रहा है कि जैसे सीवर का पानी हो। सीवर और पीने के पानी की लाईनें आपस में मिली हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि रोहतक के लोगों को यह मौलिक अधिकार मिलना चाहिए और उनको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। स्वच्छ पानी के लिए ऐसी स्कीम बनाएं कि जब बजट आए तो बजट में उसका प्रावधान हो ताकि हम उस प्रावधान के नाते जनता से इतना कह सकें कि पीने का पानी मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही सीवर की समस्या है। कहने को तो रोहतक शहर है और शहर में कहीं कोई खाली जगह नहीं होती है। हमारी मां बेटियां सवेरे शौचालय के लिए जाएं तो कहां जाएं ? अगर उनके घर में सीवर नहीं है तो उनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उसको ब्यान नहीं किया जा सकता। उनको कितनी दुर्दशा का सामना करना पड़ता है यह भी सोचने वाली बात है। हम चाहते हैं कि हर गली और हर मोहल्ले में सीवर की समस्या का समाधान होना चाहिए। जब सड़क की बात आती है तो रोहतक शहर में सड़कों का तो कहीं पर नाम भी नहीं है। सड़क में गढ्ढे नहीं बल्कि गढ्ढों में सड़क है। अगर कोई मोबिलिटी नहीं है तो फिर कैसा विकास ? मैंने पिछली बार यहां आन दि फलोर ऑफ दि हाउस भी सड़कों की दशा सुधारने के लिए कहा था और सरकार ने मुझे आश्वासन भी दिया था लेकिन वर्ष 2000 से लेकर 2005 तक मुझे कोरे आश्वासन ही मिलते रहे लेकिन उन आश्वासनों पर कभी अमल नहीं हुआ। वे सड़कें कभी नहीं बनीं। उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि वे सड़कें जो पिछली सरकार ने जानबूझ कर नहीं बनाई थीं और रोहतक के लोगों से यह कहा था कि आप लोगों ने जब हमारी सरकार को वोट नहीं दिया तो हम आपको सड़कें बना कर क्यों दें ? मेरा इस बारे में सरकार से अनुरोध है कि रोहतक शहर की सड़कों को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री किसी एक जिले के मुख्यमंत्री नहीं थे बल्कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी को एक आंख से देखना चाहिए था और सभी को सद्भावना के साथ देखना चाहिए था। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री यह कहे कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है क्योंकि इन्होंने हमें वोट नहीं दिये थे। उपाध्यक्ष महोदय, आज लोगों की आशाओं के मुताबिक बनी हुई सरकार हरियाणा प्रदेश में आई है। उपाध्यक्ष महोदय, रोहतक में बस स्टैण्ड को पुरानी जगह से उठाकर बाहर ले जाने का काम किया गया था। बस स्टैण्ड कहीं पर भी चला जाए कोई बात नहीं लेकिन आज व्यापारी को, आम आदमी को, मजदूर को उस बस स्टैण्ड तक जाने के लिए रिक्शा

[श्री शादीलाल बतरा]

के इतने पैसे देने पड़ते हैं जितने उसके बस स्टैण्ड से अपने जगह पर जाने के लिए भी नहीं लगते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि दूसरी जगहों पर जाने के लिए बस स्टैण्ड चाहे वहीं पर रहने दिया जाए लेकिन लोकल बसिज़ को पुराने अड्डे से ही चलाने का प्रबन्ध किया जाए। अगर वहां से बसें चलेंगी तो आम आदमी को, मजदूरों को और व्यापारियों को फायदा होगा और वे आराम से शहर में आ जा सकेंगे। बाहर से आए हुए लोग शहर के अन्दर आकर समान वगैरह खरीदेंगे जिसकी वजह से वहां के लोकल आदमियों को और व्यापारियों को आमदनी होगी और फायदा होगा। इसलिए मेरा सरकार से पुन: निवेदन है कि वहां पर पुराने बस स्टैण्ड और नए बस स्टैण्ड के बीच लोकल बसें चलानी चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पोल्यूशन के बारे में कहना चाहता हूं । आज शहर पोल्यूशन का अड्डा बन गया है। वहां पर जो थ्री-व्हीलर चलते हैं उनकी वजह से तो बहुत ही पोल्यूशन हो रहा है और आम लोगों के लिए बीमारी का घर बन गया है। हमारी सरकार को इस विषय में कोई न कोई नियम बनाना चाहिए ताकि पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके और आम जनता आराम से शहर में आ जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, आज एक दिशा की तरफ नहीं बल्कि अनेक दिशाओं की तरफ काम करने की आवश्यकता है, जैसे कि शिक्षा और हैल्थ है। आज हरियाणा में मैडिकल कालेज सिर्फ रोहतक में है। आज वहां पर मिडिल क्लास का आदमी जाना ही नहीं चाहता है, वहां पर अगर अमीर आदमी जाएगा तो उसको अटैण्ड कर लिया जाएगा क्योंकि वे वहां पर होने वाले खर्चों को वहन कर सकते हैं । गरीब आदमी वहां पर इसलिए जाएगा क्योंकि उसकी मजबूरी है और वह कहीं और जा नहीं सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर सुधार किया जाए ताकि वह एक अच्छा मैडिकल कालेज बन सके। उपाध्यक्ष महोदय, हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं। हम सोचते हैं कि वहां पर जाकर हमारे बच्चे अच्छे गुण और ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारे बच्चे वहां पर जाकर भटक जाते हैं। वे मुख्यधारा से हटकर शरारती तत्वों के सम्पर्क में आ जाते हैं और अपराध का रास्ता अपना लेते हैं वे आतंकवादी आदि बन जाते हैं। इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि वहां के प्रोफैसर्ज कैसे हों, वी०सी० और चांसलर कैसा हो। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस विषय पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। मेरा इस सरकार में विश्वास है कि जिस दिशा में हमारी सरकार चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि जो हमने कभी स्वप्नों में सोचा था कि हमारा हरियाणा ऐसा होना चाहिए, अब वैसा ही हरियाणा बनेगा। हरियाणा में ऐसा विकास किया जाए ताकि हमारे लोग सुरक्षित हो सकें और हरियाणा के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्रीमती अनिता यादव (साल्हावास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो माननीय गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। आज सुबह माननीय गवर्नर महोदय ने यहां पर आकर अपना जो अभिभाषण पढ़ा उसमें काफी अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है। पिछली सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए हामी भरी थी और 24 घंटे बिजली देने की बात की थी। बिजली की समस्या को लेकर अगर हम किसी आफिस में जाते थे तो वहां पर बड़ा भारी करप्शन मिलता था। पिछली सरकार ने वायदा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे और बिजली के तारों को, खम्भों को बदलेंगे लेकिन पिछली सरकार ने अपना

वायदा नहीं निभाया । पिछली सरकारों ने हमेशा प्रदेश की जनता से धोखा किया है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इतिहास को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि पिछली सरकारों ने केवल मात्र पत्थर लगाने या ओपनिंग करने के अलावा और कुछ नहीं किया इसलिए आज मैं अपनी सरकार से यह उम्मीद करती हूं कि ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज लेने के लिए जितनी भी ऐप्लीकेशंज पैंडिंग पड़ी हैं उनको तुरंत प्रभाव से क्लीयर करके कनैक्शन दिए जाएं और प्रदेश में जितनी भी बिजली की तारें गली हुई हैं उनको बदलवाया जाए। जिन मकानों के ऊपर से वायरिंग जा रही है उनको तुरंत प्रभाव से हटाकर प्रदेश की जनता को रिलीफ दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का और पानी का आपस में एक गहरा संबंध है। गर्मियाँ आने वाली हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि सबसे पहले जो बिजली की गली हुई तारें हैं उनको हटाकर दूसरी तारें लगवायी जाएं और बिजली का सुचारू रूप से प्रबन्ध किया जाए ताकि पानी से जुड़ी हुई लोगों की जो समस्या है उसका निदान हो सके।

दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा है। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने भी इस बारे में बताया है। जितनी भी प्रदेश में इंडस्ट्रीज हैं और जिनमें हमारे किसान भाईयों की जमीन गयी हुई है, मैं चाहूंगी कि उनमें उन किसान भाईयों के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारी सरकार इस बात के लिए भी प्रयासरत है कि वह बेरोजगार भाईयों को रोजगार दें। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिन किसानों के खेतों में फैक्ट्रीज लगी हुई हैं उनका मुआवजा समय के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए और उनके बच्चों को उन्हीं फैक्ट्रीज में रोजगार भी दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी हमारे आई०टी०आई०ज० डिप्लोमा होल्डर्ज हैं उनको भी इन फैक्ट्रीज में रोजगार दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार भी विधायिका थी इसलिए मैंने देखा है कि इंडस्ट्रीज में ग्रीन बिग्रेड के रूप में कुछ लोग गल्त किस्म का रोल अदा करते रहे हैं। सौ सौ रुपये का जो लालच बेरोजगारी भत्ते के रूप मे पिछली सरकार ने हमारे बेरोजगार भाईयों को दिया था वह उनके साथ एक खिलवाड़ था। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार को, अपने मुख्यमंत्री जी को यह अवगत करवाना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने हमारे बेरोजगार भाईयों को इस तरह का भत्ता देकर उनके साथ एक मजाक किया था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रदेश में जो भी नयी इंडस्ट्रीज लगे, जो भी नये अदायरे लगें उनमें हमारे बेरोजगार भाईयों को जगह दी जानी चाहिए। पिछली सरकार ने जो अच्छे वायदे और सपने लोगों को दिए थे मैं समझती हूं कि वह केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गए। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि प्रदेश में एक बहुत बड़ी स्कीम वाटर शैडस की है और उसमें करोड़ों रुपये का बजट सरकार का लगा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सालहावास में लगभग 13-14 वाटर स्कीम्ज हैं लेकिन एक भी वाटर स्कीम उनमें से चालू नहीं है जिसकी वजह से मेरे क्षेत्र के सबसे बड़े गांव मालनहेल में आज भी दो रुपये का मटका पानी मोल लेकर पिया जाता है। मैं अपनी सरकार से गुजारिश करती हूं कि गर्मियों के आगामी मौसम को देखते हुए पानी का सही रूप से वितरण हो इसलिए जो वाटर शैड स्कीम्स हैं उनको चालू कराया जाए। अनाज के निकलने का दौर शुरू हो गया है। मेरे सालहावास विधान सभा क्षेत्र में कोसली एक छोटी सी मंडी है। पिछली सरकार के समय में मैंने इस मंडी के बनाए जाने के बारे में आवाज उठाई थी लेकिन वह ****** थी जिसने वह मंडी भी नहीं बनाई। उन्होंने मुझे कभी खुलकर बोलने का मौका ही नहीं दिया। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि जो मंडियों का बारदाना है और

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया गया।

[श्रीमती अनीता यादव]

जो अनाज और सरसों की खरीद है वह हमारे यहां के ही किसान भाइयों से की जाए क्योंकि दूसरी जगह के व्यापारी कोसली मंडी में आकर अपनी फसल बेचकर चले जाते हैं। और हमारे यहां के किसान मुंह ताकते रह जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि हमारे यहां के किसान की फसल का एक एक दाना और उसके बारदाने का सही प्रयोग किया जाए। जहां तक प्रदेश में ला एंड ऑर्डर की बात थी उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि पिछली सरकार के समय में बड़ा भारी गदर मचा हुआ था। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। आज हमारे प्रदेश में हमारे विधायक इतने सभ्य ढंग से लोगों ने चुनकर भेजे हैं कि सभी इस बात का ख्याल करते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जो हमारे प्रशासन के अधिकारी बैठे हुए हैं उन सभी से मैं यह गुजारिश करती हूं कि वे ला एंड ऑर्डर की ऐसी व्यवस्था कायम करें कि जैसे भगवान राम चन्द्र जी का राज हो गया हो।(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।) अध्यक्ष महोदय, मैं यही गुजारिश करना चाहती हूं कि हमारे कांग्रेस के राज में प्रदेश में एक ऐसी कानून व्यवस्था हो, जिसका सभी अनुसरण करें । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अनीता जी, अब आप वाइंड अप करें।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी बोलते हुए केवल दो मिनट का समय ही हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैं अपने चैंबर में आपकी आवाज सुन रहा था। Please take your seat Smt. Anita Ji, (Interruptions) No I am very sorry. Thank you very much. (Interruptions)

श्री रमेश कुमार गुप्ता (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं। जो भी कल्याणकारी योजनाएं इस सरकार द्वारा घोषित की गई हैं वे सभी बहुत बढ़िया हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत सारी बातें सदन के सामने लाई गई हैं। मेरे एक साथी विधायक साहेब ने बताया मैं भी उस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछली सरकार द्वारा हाउस टैक्स कई गुना बढ़ा दिया गया । जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनके ऊपर हाउस टैक्स का लगभग 20-30 गुना हाउस टैक्स लगा दिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हाउस टैक्स प्रपोर्शनेट रेट में बढ़ाया जाए और जो बढ़ा हुआ टैक्स है उसको कम किया जाए। एक पीले और गुलाबी कार्ड की बहुत ज्यादा समस्या है जो हमारे को इलैक्शन में देखने को मिली, इसका भी दोबारा व्यापक सर्वे होना चाहिए और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए ये कार्ड ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिएं।

Mr. Speaker : Now, Mr. Karan Singh Dalal will speak. I know Dalal ji, you are a good orator. But because of the paucity of time, you will be given only 5 minutes. No more time will be allowed. (noise & Interruptions) Please go ahead, now.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदय ने पढ़ा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हरियाणा के अन्दर नई सरकार बनी है। हरियाणा के लोगों ने इतना बड़ा बहुमत कांग्रेस पार्टी को दिया है। इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने हरियाणा के लोगों की दुख तकलीफों के बारे में

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY

चिन्ता जताई है। महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण में जो बातें कहीं हैं वे बहुत अच्छी बातें हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस बारे में आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर ही नहीं, तमाम हिन्दुस्तान और दुनिया के दूसरे कोनों में बैठे लोग जो हरियाणा में रुचि रखते हैं वे यही जानना चाहते हैं कि हमारी नई सरकार पिछली सरकार के मुखिया ओमप्रकाश चौटाला के शासन के समय, उनके परिवारजनों तथा अधिकारियों द्वारा जो गलत काम हुए हैं, उनके बारे में क्या करने जा रही है ? अध्यक्ष महोदय, जिन मर्यादाओं को ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने लांघा है ऐसी मिसालें देश में तो क्या दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने मेरे बारे में समय का अभाव कहा है इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सीमित समय के अन्दर ही मेरी बातें रिकार्ड पर आ जाएं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला आजाद हिन्दुस्तान के पहले मुख्यमंत्री थे जिनके खिलाफ किसी और व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि उनके सगे भाई द्वारा एक एफ०आई०आर० दर्ज करवाई गई थी। उनके भाई प्रताप सिंह ने इस एफ०आई०आर० में उनके खिलाफ आरोप लगाये थें कि किस तरीके से ओमप्रकाश चौटाला ने जब उनके पिता चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे किस तरीके से हरियाणा प्रदेश का खजाना ** कौन-कौन सी जायदादें ओम प्रकाश चौटाला जी ने *** की मार्फत बनाई। बाद में ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि उस एफ०आई०आर० जो उनके अपने विरूद्ध थी अपनी मर्जी का आई० ओ० को लगाकर उसको वापस ले लिया और उन तमाम मुकदमों को उन्होंने खराब किया और अदालत में यह साबित कर दिया कि यह मुकदमा चलाने के योग्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि न केवल उस मुकदमें की बल्कि पिछले साढ़े पांच साल के शासनकाल के दौरान ओमप्रकाश चौटाला की सरकार ने जो हरियाणा में भ्रष्टाचार के नये आयाम कायम किये हैं उनकी जांच हो। अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय और बड़ी-बड़ी संस्थायें बड़ी रिसर्च करके देश के योगदान में नई बातों को लाने की कोशिश करती हैं लेकिन श्री ओमप्रकाश चौटाला जी ने भ्रष्टाचार फैलाने के तरीके ईजाद करके प्रदेश के लोगों के सामने खड़े कर दिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का 36 बिरादरी का नौजवान जो मेहनत करके पढ़ना चाहता था वह उम्मीद करता था कि विश्वविद्यालयों में जाकर, कालेजों में जाकर पढ़ाई करके अपनी मेहनत व लगन से हरियाणा की नौकरियों को प्राप्त करेगें लेकिन ओमप्रकाश चौटाला और उनके दोनों बेटे जे०बी०टी० के दाखिलों का मूल्यांकन खुद करते थे। जब जे०बी०टी० कोर्स के लिए दाखिला होता था तो उसकी लिस्ट ओमप्रकाश चौटाला और उसके दोनों बेटे तैयार करते थे कि किस लड़के को इस कोर्स में दाखिला देना है। एच०पी०एस०सी० की बात का माननीय श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, आज मैंने अखबार में पढ़ा कि एच०पी०एस०सी० के सेक्रेटरी का तबादला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कितने अफसोस की बात है कि एच०पी०एच०सी० द्वारा जो एच०सी०एस० के पद भरने के लिए एग्जाम लिया जाता है उसका सारा कन्ट्रोल, एच०पी०एस०सी० का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन करता है, सरकार इसको इसी बात की तनख्वाह देती है लेकिन चौटाला साहब ने उसको तो घर बैठा रखा था और एच०पी०एस०सी० के सेक्रेटरी खुद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का सारा काम करते थे। वे अपनी गाड़ी में बैठाकर कापियों का मूल्यांकन खुद करवाया करते थे। जो उनकी मर्जी के कैंडीडेटस थे उनको पास कर दिया जाता था। जो लोग उनको धन देते थे वे उनकी सिलेक्शन के लिए सिफारिश करते थे। मुख्यमंत्री, विधायकों और उनके रिश्तेदारों को एच०सी०एस० बनाया जाता था। अध्यक्ष महोदय, सर्विस देने के मामले में पहली दफा हरियाणा के शड्यूल्ड कास्ट

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से एक्सपंच कर दिया गया।

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

और बैक्वर्ड क्लास के भाईयों के साथ ज्यादती हुई है, नहीं तो पहले कई वर्षों से ऐसा होता रहा है कि जिसमें हरियाणा के हरिजन क्लास का कोई भाई अच्छे नम्बर पाता था और वह अपनी मैरिट से एस०सी० कैटेगरी की बजाय जनरल कैटेगरी में चयनित होता था और वह एस०सी० कैटेगरी का कैंडीडेट नहीं माना जाता था। अध्यक्ष महोदय, चाहे तो रिकार्ड मंगाकर देख लें, ओम प्रकाश चौटाला ने किसी एस०सी० भाई को मैरिट के आधार पर भी रिजर्व कैटेगरी से अलग नहीं जाने दिया। कितना बड़ा अन्याय उनके साथ किया गया ? अध्यक्ष महोदय, आज आपके माध्यम से कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसमें बताया गया है कि वर्ष 1999 तक 12 हजार करोड़ रुपये का कर्जा हरियाणा के ऊपर था जो कि 2004 में 22 हजार करोड़ रुपये हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने परिवार की राजनीति को चमकाने के लिए कभी राजस्थान से चुनाव लड़ा और कभी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा। आज इस बात की जांच होनी चाहिए कि हरियाणा में कितना बाजरे का उत्पादन हुआ था और हरियाणा की मंडियों में कितना बाजरा खरीदा गया ? ओम प्रकाश चौटाला के लोग राजस्थान से कम दाम पर बाजरा खरीद कर उसी बाजरे को सरकारी रेट पर ज्यादा रेट पर हरियाणा की मंडियों में बेचा करते थे और अरबों खरबों रुपया कमाया करते थे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की मंडियों से गेहूं सस्ते दामों पर खरीद कर उसी गेहूं को हरियाणा के दाम पर मुनाफा कमा कर ज्यादा रेट पर हरियाणा की मंडियों में बेचा करते थे और वह गेहूं आज भी मंडियों में पड़ा हुआ सड़ रहा है बहुत ज्यादा कर्ज ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के लोगों पर खड़ा करके रख दिया है। अध्यक्ष महोदय, यहां मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और आज उन्होंने जवाब भी देना है। आज हरियाणा के नौजवान यह जानना चाहते हैं कि हरियाणा की पिछली सरकार ने नौकरियों के चयन में HPSC ने जो **** की, SSB ने जो **** की, यूनिवर्सिटीज, मैडीकल कालेजिज़ और आटोनॉमस बॉडीज में उन्होंने जिस तरीके से सिलैक्शन करवाया है हरियाणा की सरकार उनका क्या फैसला लेने जा रही है ? जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की सरकार ने PPSC के उन तमाम अधिकारियों को जेल में डालकर उनसे उन तमाम बातों को उगलवाया आज हरियाणा को भी उसी रास्ते पर चलने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, अगर यह नहीं हुआ तो हरियाणा के नौजवानों को बहुत बड़ी निराशा होगी। जो बच्चे पढ़ लिखकर इस प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं उनके भरोसे को कायम करने के लिये यह सरकार पिछली सरकार को दण्डित करने की बात केवल मन में न रखे बल्कि दोषियों के खिलाफ एक्शन लें ताकि आने वाले समय में उन सब लोगों को एक पाठ और सबक मिले कि कोई भी व्यक्ति नौजवानों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करेगा तो उनका हश्र भी वही होगा। हरियाणा की सरकार को यह बताना चाहिए कि इस बारे में वे क्या करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश के अन्दर जो देशभक्त रहे हैं, वे वीर शहीद जिन्होंने इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हम उनका आदर करते हैं, उनके बुत लगने चाहिएं, प्रदेश में ऐसे लोगों के बुत लगने चाहिएं, या उन स्वतंत्रता सेनानियों के बुत लगने चाहिएं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के लिए सब कुछ न्यौछावर किया । चौ० देवीलाल के बुत आज हरियाणा में जगह जगह लगे हुए हैं। इस विधान सभा में यह ब्यौरा आना चाहिए कि तमाम ऐसे बुतों पर किस हैड के तहत पैसा खर्च हुआ ? यह हरियाणा की सरकार का और जनता का पैसा लगा है। यह किसी के बाप की बपौती नहीं थी कि जहां मर्जी आई बुत लगा दिए। आज हरियाणा की जनता इस

* चेयर के आदेशानुसार एक्सपंज कर दिया गया।

बात को जानना चाहती है इन बुतों को लगाने के लिए पता नहीं किस हैड के तहत पैसा आता था, कौन उनके टैण्डर्ज भरता था, और किस आधार पर उन बुतों को लगाया जाता था ? जनता केवल इसलिए नहीं जानना चाहती कि ये चौ० देवीलाल के बुत हैं बल्कि इस लिए जानना चाहती है कि आने वाले समय में हरियाणा की धरती पर कोई ऐसा आदमी दोबारा न पैदा हो जाए तो अपने परिवार की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए मनमाने तरीके से इस हरियाणा को हांकना चाहे। इसी तरीके से भ्रष्टाचार के बारे में भी सरकार को देखना होगा। हमारे फरीदाबाद में 90 हजार बड़ी-2 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि मुख्यमंत्री ने अपने चहेतों को वहां डी०टी०ओ० लगाया। वे डी०टी०ओ० सरेआम एक गाड़ी से 2 हजार रुपये एकत्रित करके जितना धन उनका बनता था अपने पास रखते थे और उस धन में से मुख्यमंत्री के पास भी भेजते थे, आज उस धन की जांच होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री महोदय जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि केवल फरीदाबाद के अन्दर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और इस तरीके से सरकार के खजाने को *** गया है। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से यमुनानगर में जो थर्मल पावर प्लांट बन रहा है उसके टैण्डर के साथ भी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने छेड़खानी करने की कोशिश की। रिलायंस कम्पनी के साथ यह टैण्डर हुआ है जिसमें उन्होंने छेड़खानी करने की कोशिश की और प्रदेश के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस बारे में मैं आदरणीय जिंदल साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्लांट की फाईल मंगवाएं और देखें कि किस प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला जी ने उस फाईल के साथ छेड़खानी की और सरकार के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार द्वारा सरकारी हस्पतालों में जो भी मरीज बीमारी को चैक करवाने के लिए जाता था उससे पांच रुपये पर्ची के और 100 रुपये भर्ती होने पर बैड के चार्जिज लगा दिये थे। मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इस गलत आदेश को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाये। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं थाईंड अप कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि तेजेन्द्र पाल मान जी ने कहा मैं भी मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अकेले उन राजनेताओं को सजा देना काफी नहीं होगा जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया बल्कि जो अधिकारी उनके साथ भ्रष्टाचार में शामिल थे, चाहे वे किसी भी जाति के हों अथवा किसी गुट से संबंध रखते हों जिन्होंने पिछले शासन में मर्यादाओं को लांघकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में है।

Mr. Speaker : Please wind up Mr. Dalal. No doubt, you are talking excellent. But I have to accommodate everybody.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Speaker Sir, I have to make a submission. Mr. Dalal was rightly saying केवल एक टैण्डर की बात नहीं है जितने भी बड़े-बड़े टैण्डर थे जिनमें करोड़ों रुपये की बात होती थी वे सिंगल टैण्डर अलॉट हुए हैं। अधिकारी हाथ जोड़ देते थे कि हम नहीं कर सकते लेकिन फिर भी उनसे करवाया जाता था। पिछली सरकार हर कदम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थी।

* चेयर के आदेशानुसार एक्सपंज कर दिया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, भुलाना जी ने भी कहा कि पिछली सरकार के मुखिया ने हर कदम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। शराब के ठेकों की नीलामी में भी पिछली सरकार द्वारा बहुत अधिक बेईमानी की गई। ट्रिब्यून में एक बहुत अच्छा आर्टिकल इस बारे में लिखा गया था और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की रूलिंग उसमें दी गई थी जिसमें यह जिक्र किया गया था कि जिस तरीके से ठेकों की बोली छोड़ी गई है वह गलत है लेकिन चौटाला साहब ने उसकी परवाह नहीं की। पानीपत थर्मल प्लांट जहां पर अरबों रुपये का कोयला खरीदा जाता है उस बारे में भी इंगलिश ट्रिब्यून के फ्रंट पेज पर खबर छपी थी कि घटिया किस्म का कोयला खरीदा गया है और उस थर्मल प्लांट को इससे नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके तमाम अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यदि सरकार को सबूत चाहिएं तो तमाम सबूत मेरे पास हैं। अंत में मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा (मुण्ढाल खुर्द) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो जो अभिभाषण आज सुबह राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़ा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। साथ ही साथ सरकार ने मात्र एक महीने से कम समय में जो अपनी इच्छा जाहिर की है, उसका स्वागत करता हूं। यह स्वागत न केवल मैं करता हूं बल्कि सभी प्रदेशवासी करते हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स डिपार्टमैंट को सभी साथियों ने बोलते हुए बिल्कुल छोड़ दिया। जब कभी कोई एशियाड या ओलम्पिक गेम्ज होते हैं तो हम बात करते हैं कि इतनी कम आबादी का कोई देश है जिसके पास कई मैडल्ज हैं लेकिन हिन्दुस्तान की कितनी अधिक आबादी है लेकिन फिर भी हमारे पास कोई मैडल नहीं। यहां पर न किसी के पास गोल्ड मैडल है, न सिल्वर मैडल है और न ब्राउन्ज मैडल है। इन मैडलों के बारे में हम उस वक्त बात करते हैं जब कोई खेल कम्पीटिशन होता है। जब कोई काम करने का समय आता है तो हम सब उसको नजर अंदाज कर देते हैं। इस बारे में मेरा कहना है कि उन स्टेशन्स को आइडैन्टीफाई करें कि कहां कहां पर हम स्टेडियम बना सकते हैं ? वे स्टेडियम इन्टरनैशनल लैवल के हों। ऐसे स्टेडियमों की हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए ताकि आने वाले 10 सालों में नतीजे आ सकें। केवल ओलम्पिक गेम्ज के लिए बिल्डिंगें बनाने से कोई खिलाड़ी नहीं बन जायेगा और न कोई ऐथलीट बन जायेगा। मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए आज से प्रावधान रखा जाए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हम स्पोर्टस और हैल्थ को एक साथ इकट्ठा कर लें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि हैल्थ और स्पोर्टस की पालिसी सही हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हैल्थ में हमारी पालिसी बिलमुल रहती है। स्पीकर साहब, अब तक जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें कहीं हैं। मेरे से पहले जितने भी वक्ता बोले उन्होंने उन्हीं बातों का जिक्र किया जो बातें हम चुनाव से पहले लोगों के बीच कहा करते थे। यहां पर आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये चीजें भी हमें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री जी इस बारे में थोड़ा लीक से हटकर काम करें। कई बातें ऐसी हैं कि जब हम पब्लिक के सामने जाते हैं तो हम जवाब नहीं दे सकते। उस वक्त हमें यही कहना पड़ता है कि कानून ही ऐसा है कि ये बातें ऐसे ही चलेंगी। अभी कुछ समय पहले मेरे एक लायक दोस्त ने कहा था कि सिर्फ एम०एल०आर० के 100/- रुपये लगते हैं। स्पीकर साहब, एम०एल०आर० बनती है लेकिन कितने में बनती है, यह आपको भी पता है, मुख्यमंत्री महोदय को भी पता है और

दूसरे मेम्बरान को भी पता है। अगर पिछले 5 सालों की तरह अब भी वैसे ही बनेगी तो लोग हमें कहेंगे कि आप लोग तो पहले भुक्ते हुए थे और भुक्तभोगी थे, उसके बाद भी ऐसा कैसे हो रहा है ? अब मैं इलैक्ट्रीसिटी के बारे में कहना चाहूंगा, जब सारे हरियाणा को इलैक्ट्रीफाई किया गया था तो उस समय हमारी आबादी बहुत थोड़ी थी। अब प्रत्येक गांव चारों तरफ बढ़ चुका है। हर शहर भी बढ़ चुका है। जो गरीब लोग हैं उनके मकानों के ऊपर से बिजली के तार गए हुए हैं। किसी गांव में भी चले जाएं प्रत्येक गांव में यह समस्या है और जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि इसके लिए ऊपर से बात करनी होगी क्योंकि हमारे पास ग्रान्ट नहीं है इसलिए इसको हम अलाऊ नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, समय के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। उन गरीबों का क्या दोष है जो सुबह अपनी छत पर न जा सकते हों और सर्दी के मौसम में धूप भी न सेंक सकते हों। मैं कई बातें कहना चाहता हूं। अभी मान साहब ने पीले और गुलाबी कार्ड के बारे में कहा। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि उनके बारे में ध्यान दें और उनको फिर से रिव्यू करवाएं।

अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के बारे में जितना कम्पनसेशन सरकार ने मंजूर किया है वह मैं पेपर में पढ़ता हूं, वह बहुत ही थोड़ा है। यह तो सिर्फ बीज का पैसा ही है इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि पहले तो वहां पर हम गिड़गिड़ा कर अधिकारियों की मार खाते हैं कि गिरदावरी कितनी हुई। अगर 80 परसैंट लौस है तो 40 परसैंट लौस दिखाएंगे। इस प्रकार से 40 परसैंट लौस तो वहीं रह गया। यहां आकर हमारे रूल्ज ऐसे हैं कि 1000,1200, 1250 या 1500 रुपये का कम्पनसेशन देते हैं। मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करता हूं कि जहां पर ओलों से लोगों की फसलों का नुकसान हुआ है वहां पर हमें मैकसिमम कम्पनसेशन को देना चाहिए क्योंकि उनके पास कमाई का और कोई चारा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस कुछ फसल की खरीद करते हैं और उनका भाव भी तय करते हैं लेकिन उन फसलों को खरीदने वाली कोई एजैंसी नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरकारी एजैंसी सरसों को भी खरीदे ताकि जमीदारों को अपना पैसा मिल सके। समय कम होने के कारण मैं और बात नहीं कह पा रहा इसलिए अन्त में मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, जितने हमारे साथी हैं खासतौर पर दक्षिण हरियाणा के साथियों ने पानी की समस्या के बारे में अपने विचार रखे हैं । मैं इसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पहली बार साऊथ हरियाणा के किसी व्यक्ति को यह काम दिया है। मैं अपने साथियों को आश्वासन देना चाहूंगा कि इस बारे में जो सबसे पहला मुद्दा है वह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आफ वाटर है। मैं इसके बारे में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पीने के पानी की समस्या है। वहां पर एक मसानी बैराज बना हुआ था उसको भरने की बात भी की जायेगी और उसके रि-चार्जिंग की बात भी की जाएगी। इसी प्रकार से हमीदपुर जो बांध है उसके बारे में भी हम 14.00 बजे कोशिश करेंगे कि वहां पर पानी लाया जाये। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पानी पीछे से आ रहा है उससे रि-चार्जिंग भी करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आफ वाटर के लिए हमें एक और कैरियर वाटर चैनल भी बनाना पड़ेगा। हमारा जो दक्षिणी हरियाणा का पानी है उसके लिए सरकार एक स्कीम बना रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि नरवाना ब्रान्च के साथ ही साथ एक और पैरलल चैनल बनाई जाए जिससे कि साऊथ हरियाणा में पानी जा सके। इसके लिए बाकायदा हम एक अच्छी स्कीम बना रहे हैं। मैं कहना

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

चाहूंगा कि जो यमुना बेसिन है वहां वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने पानी के लिए काफी सफर किया है और जो स्कीम बनाई जा रही है उसमें न केवल दक्षिणी हरियाणा बल्कि कैथल के ऐरिया को भी फायदा होगा और जीन्द के इलाके को भी उसका फायदा होगा। केवल साऊथ हरियाणा ही नहीं इससे काफी और जिलों को फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके आलावा माननीय श्री सुरजेवाला जी ने भी कुछ मुद्दे उठाए थे। एक तो उन्होंने कैपटिव पावर का मुद्दा उठाया है। मैं इसके बारे में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम एक पायलट प्रोजैक्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे ताकि उससे लाईन लौसिज भी कम हों। हमारी कोशिश है कि लिफ्ट इरिगेशन की जो स्कीम्ज हैं वहां पर कैपटिव पावर प्लांट लगाए जाएं और छोटे पावर प्लांट्स बनाएं जाएं। 25-25 मेगावाट या 100-100 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। इन पर इंस्टॉलेशन चार्जिज तो कम होंगे ही इसके साथ ही पावर लॉसिज भी कम होंगे। हम डिपार्टमैंट से बात करके कोशिश करेंगे कि इस तरह का काम किया जाए जिससे लाईन लॉसिज भी कम हों तथा पावर के मामले में हम सैंट-पर-सैंट इन्डिपैंडैन्ट हो जाएं और हमें पावर डिपार्टमैंट पर डिपैंड ऑन न करना पड़े। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ माननीय श्री सुरजेवाला जी ने बीबीपुर लेक के बारे में बात कही है। मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि यहां पहले बहुत वाटर स्टोरेज हुआ करता था। इस बात को लेकर वहां पर किसानों ने काफी विरोध किया था हम पूरी तरह से इसको एग्जामिन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उससे लोगों को फायदा हो सके। अध्यक्ष महोदय, यहां पर कन्टैमिनेटिड वाटर के बारे में खासतौर से कहा गया है। फरीदाबाद का जो हमारा ऐरिया है वहां पर पोल्यूटिड वाटर जा रहा है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने पहले भी इसे बारे में बाकायदा दिल्ली गवर्नमैंट को as a matter of protest का एक लैटर भी भेजा था कि वे इतना गन्दा पानी वहां पर भेज रहे हैं यह ठीक नहीं है। हमने उनको यह भी लिखा है कि वे वहां पर ट्रीटमैंट प्लांट भी लगाएं। आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल की वाटर क्वालिटी बहुत ही खराब आ रही है उस में सुधार के बारे में हम दोबारा कोशिश करेंगे और मामले को बाकायदा यू०पी० के साथ टेकअप करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर आगरा कैनाल को टेकओवर करने की बात आई। यह दो स्टेट्स के बीच का मामला है उसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री और स्टेट गवर्नमैंट कोशिश करेंगे कि इसका चार्ज हमारे हाथ में आ जाए। दूसरे एस०वाई०एल०के अंरली कम्पलीशन के बारे में मुख्यमन्त्री महोदय अपने जवाब में बता देंगे। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बारे में हमारे साउथ हरियाणा के जितने भी लोग हैं वे यह चाहते हैं कि एस०वाई०एल०का पानी हमें जल्दी मिले हम लोगों ने इसके लिए काफी सफर भी किया है। इसको बनवाने के बारे में केस सुप्रीमकोर्ट में है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमें जल्दी ही पानी मिलेगा लेकिन पिछले दिनों पंजाब गवर्नमैंट ने स्टेटमैंट दी कि हम बातचीत से मसले को हल करेंगे यह एक अच्छी बात है। मैं यह कहना चाहूंगा कि 1981 में इन्दिरा जी के द्वारा जो एग्रीमैंट हुआ है उसको उन्होंने रि-अपील कर दिया। उनका पहला कदम यह होना चाहिए कि वे उसको रिस्टोर करें। हमारा जो पहला एग्रीमैंट था उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए उसके बाद दोबारा से बातचीत की बात करें। जो एग्रीमैंट पहले हुआ था वह भी तो बातचीत के बाद ही हुआ होगा। जब बातचीत के लिए माहौल बनेगा तो बात हो सकती है लेकिन उसके लिए पंजाब, जो कि हमारा बड़ा भाई है, को पहल करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, हमें पूर्ण यकीन है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरा न्याय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना था, धन्यवाद।

डा० शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव पर सहमति के उपरान्त मैं वर्तमान कांग्रेस सरकार को बधाई भी देना चाहूंगा क्योंकि यह सरकार हरियाणा प्रदेश में यह संदेश देने में सफल हुई है कि प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आगे आएगा। इससे प्रदेश के लोगों को आशा की एक किरण दिखाई दी है। अध्यक्ष महोदय, यदि हम स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध हरियाणा की कल्पना करते हैं तो हमें कुछ बेसिक इशूज ऐड्रेस करने पड़ेंगे। मैं केवल चार प्वांयट्स बताउंगा और माननीय मुख्यमन्त्री जी से यह अनुरोध करुंगा कि वे इस बारे में थोड़ा ध्यान दें। जो बेसिक इशूज हैं वे ये हैं कि हर घर में स्वच्छ पानी होना चाहिए। हर गृहणी जब अपने घर में भोजन बनाए या कुछ और काम करे तो उसको स्वच्छ पानी उपलब्ध होना चाहिए जिससे वाटर बॉर्ण्ड डिसीजिज़ दूर हो सकती हैं, हर घर में स्वच्छ लैट्रिन होनी आवश्यक है। शौचालयों की समस्या के बारे में हमारी बहनों ने भी जिक्र किया है और बताया है कि यह समस्या कितनी गम्भीर है, दूसरे वक्ताओं ने भी इस बारे में बात की है। इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए इसका निदान होना चाहिए। मेरा तीसरा प्वांयट यह है कि हर बच्चे को स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए और कम से कम बारहवीं क्लास तक शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। वह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार दिला सके। शिक्षित हो कर चाहे कोई नर्स बने, चाहे कोई लैब-टैक्नीशियन बने, चाहे कोई मोटर या स्कूटर मकैनिक बने, और चाहे कोई पेंटर बने मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी शिक्षा जिससे बच्चों को रोजगार मिल सके हर बच्चे को मिलनी चाहिए। मेरा चौथा प्वायंट यह है कि हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। हरियाणा में हर वर्ग को और हर जाति को उसका हक मिले। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज जिसके पास कुछ है तो उसको और मिलेगा और जिसके पास कुछ नहीं है तो उसको भी कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, अगर ऐसा होगा तो ही हम कह सकेंगे कि सोसाइटी में प्रोगैस हो रही है। मेरे से पहले बोलते हुए यादव साहब ने भी कहा है और मैं भी भिवानी के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं । स्पीकर सर, भिवानी में मैडीकल कॉलेज का पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है और वहां पर मैडीकल कॉलेज खोलने पर सरकार के उपर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा। इसलिए सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। स्पीकर सर, भिवानी अस्पताल की तरफ जाते वक्त रास्ते में एक रेलवे फाटक आता है और मुझे नहीं लगता है कि वह 24 घंटे में से 12 घंटे भी खुलता होगा। वहां पर अगर कोई एक्सीडैंट हो जाए तो फाटक बंद होने की वजह से मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता है और वह फाटक पर ही दम तोड़ देता है। अगर कोई औरत प्रैगनैंट हो और उसकी डिलीवरी का समय नजदीक आ जाता है तो कई बार उसकी डिलीवरी भी फाटक बंद होने की वजह से वहीं पर हो जाती है। ऐसी घटनाएं वहां पर कई बार हो चुकी हैं। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उस फाटक पर एक ओवरब्रिज बनवाने का कष्ट करें ताकि वहां पर लोगों को सुविधा प्रदान हो सके। स्पीकर सर, भिवानी में एक व्यापारी लड़कियों का स्कूल बनाने के लिए तैयार है । अगर वहां पर सरकार की तरफ से जमीन मिल जाएगी तो वहां पर लड़कियों का भी स्कूल बन जाएगा। स्पीकर सर, मेरे से पहले बोलते हुए जैसा कि नरेश भाई ने कहा है और लोगों की भी मांग है कि वहां पर एक मैडीकल कालेज बनाया जाए। इस पर सरकार गौर करने का कष्ट करे। स्पीकर सर, मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी आखिरी बात कहना चाहूंगा क्योंकि आप बार-बार कह रहे हैं कि समय का ध्यान रखा जाए। मैं बाकी का समय अगली दफा ले लूंगा। इसके अलावा स्पीकर सर, किसी भाई ने प्राईवेट डाक्टर्ज के बारे में टिप्पणी की थी लेकिन मैं उनकी उस टिप्पणी से सहमत नहीं हूं। स्पीकर सर, उस भाई की उस टिप्पणी को

[डा० शिव शंकर भारद्वाज]

सदन की कार्यवाही से एक्सपंज कर देना चाहिए। स्पीकर सर, प्राईवेट स्कूलों और प्राईवेट डाक्टर्ज के बिना आज हरियाणा का गुजारा नहीं हो सकता है इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

श्री सुखबीर सिंह (रोहट) : स्पीकर सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा ध्यान रखा। स्पीकर सर, सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और उस पर बहुत से सदस्य मेरे से पहले बोले हैं। सभी ने चौटाला साहब के वक्त में उनके द्वारा हुए भ्रष्टाचार के बारे में बात की है। मेरा इस विषय में यह कहना है। कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए और अगर वे कसूरवार हों तो सबको उस बारे में पता चलना चाहिए। जब तक कसूरवार को सजा नहीं मिलेगी तक तक उसको शिक्षा नहीं मिल सकती। अभी सदन में कई साथियों ने दक्षिणी हरियाणा की बात की है कि वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सोनीपत इलाके में एक भी गवर्नमैंट कॉलेज नहीं है। वहां नहरों में 42-42 दिनों बाद पानी आता है। (विघ्न) गवर्नमैंट कॉलेज होना अलग बात है और इंजीनियरिंग कॉलेज अलग बात है। स्पीकर सर, खरखौदा में आज तक कोई भी बस स्टैंड नहीं है और वहां पर यात्रियों को बरसात में भीगना पड़ता है और अगर गर्मी होती है तो उनको गर्मी में वहां पर खड़े रहना पड़ता है। स्पीकर सर, खरखौदा में हजारों यात्री होंगे जो रोज दिल्ली नौकरी करने के लिए जाते हैं। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि सभी सरकारों के वक्त में उन्होंने दिल्ली तक बस चलाने के लिए एप्लीकेशन दी हैं लेकिन आज तक वहां से दिल्ली के लिए एक भी बस नहीं लगी है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल ही इन्होंने सोनीपत में फोन किया और उनको कहा है कि वहां पर बस लगा कर इन्हें दो-तीन दिनों में रिपोर्ट करें। इस तरह से अगर सरकार काम करेगी तो मेरे हिसाब से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सरकार कम से कम बीस साल चलेगी किसी और सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतने ईमानदार आदमी आ जाएंगे तो औरों की क्या जरूरत है ? अध्यक्ष महोदय, सभी ने पीले कार्ड के बारे में भी यहां पर चर्चा की। चौटाला सरकार ने गरीबों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया बल्कि उन्होंने तो पूरी तरह से गरीबों का शोषण किया है। अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी की जो सेवा करता है यह क्लीयर कट बात है कि उसका अहसान गरीब आदमी डबल सेवा करके उतारता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि गरीबों को प्लाट जरूर मिलने चाहिएं। सरकार की तरफ से हर जगह जमीन एक्वायर की जानी चाहिए और गांव में जिनके पास जमीन नहीं है उनको स्पैशल प्लॉटस दिए जाने चाहिएं। अफसर विधायकों के पास आएं और विधायक अफसरों के साथ जाएंगे और जाकर खुद जांच करवाएंगे। असलियत में जो गरीब हैं उनके पीले कार्ड बनने चाहिएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ए०बी०सी० कम्पनी का राज चला करता था। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि एम०एल०एज० को अपने अपने हल्कों में काम करवाने के लिए लोकल डिवल्पमैंट फंड जरूर दिया जाना चाहिए। एम०पी० को भी दो करोड़ रुपया मिलता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस बारे में उदारता दिखानी चाहिए और सबको दिखाना चाहिए की हमने यह शुरूआत की है। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि 90 के 90 एम०एल०एज० चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि देवीलाल जी ने पैंशन के सौ रुपये किए थे। गांवों में चर्चा चलती रहती है कि यह तो देवीलाल पैंशन है। हमने लोगों को बहुत समझा लिया कि आज तक किसी संस्था को देवीलाल परिवार ने अपनी जेब से अगर दान दिया हो तो बताएं लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सौ रुपये पैंशन और बढ़ा दी जाए ताकि पैंशन

के साथ उनका नाम हट जाए। अगर 1991 में कांग्रेस सरकार 200 रुपये कर देती तो देवीलाल जी का पैंशन से नाम हट जाता या बाद में चौधरी बंसीलाल के समय में 50 रुपये भी बढ़ा दिए जाते तो भी उनका नाम इस योजना से हट सकता था। अध्यक्ष महोदय, मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि अगर एक लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दो तो पहली लकीर अपने आप छोटी हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह काम भी होना चाहिए। इसके अलावा सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने जा रही है। ओचन्दी बोर्डर पर जो औद्योगिक एरिया बसने लग रहा है। उसका परिजोन किया जाना चाहिए। इसके अलावा खरखौदा में जो लड़कियों का कॉलेज है उसको सरकार अपने अधीन लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक प्वायंट को क्लीयर करना चाहती हूं। यह बड़ी भ्रान्ति है बड़े दुख की बात है कि लाखों लोगों ने जिनको चुनकर भेजा है उनके मन में भी यही बात है। अध्यक्ष महोदय, पैंशन का जहां तक सवाल है, सभी माननीय सदस्यों को यह ध्यान होना चाहिए कि यह बुढ़ापा पैंशन जब राजाओं महाराजाओं के प्रिवीपर्स खत्म हुए थे तो उसके बाद फ्रीडम फाइटर्ज को पैंशन दी जानी शुरू की गयी थी और जो धन बचा था उससे असहाय और गरीबों को पैंशन देने की स्कीम श्रीमती इंदिरा गांधी ने शूरू की थी। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि पहले यह 60/- रुपये थी। जब मैं 1986 में सोशल वैल्फेयर मिनिस्टर थी तो शुरजेवाला जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने सैंट्रल गवर्नमैंट को यह सिफारिश की थी कि यह 60 रुपये की राशि कम है इसलिए इसको सौ रुपये किया जाना चाहिए। 1987 में देवीलाल जी की सरकार आयी तो उनको 60 रुपये की जगह 100 रुपये एनाउंस करने का मौका मिल गया। मैं यह नहीं कहती कि उन्होंने घर से की या क्या की लेकिन यह कहना कि यह पैंशन देवीलाल जी ने दी, यह कहना बिल्कुल गलत है। पैंशन देनी तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू की थी।

चौ० अर्जन सिंह (छछरौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। वैसे तो सारी बातें हमारे सीनियर साथियों ने रख दी हैं यदि मैं उनको दोबारा दोहराना चाहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे साथियों ने जो बातें कही हैं मैं उन सभी बातों से सहमत हूं। मेरा आपसे और मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध है कि मेरा हल्का जहां से मैं चुनकर आया हूं वह तीन राज्यों से उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश से लगता है। मैं चाहता हूं कि हमारी स्टेट की बाउंड्री ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बाहर से आने वाले को ऐसा लगे कि बहुत ही अच्छा राज्य है। जब चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसा ही उदाहरण बना था। शुरजेवाला जी ने एक समस्या रखी थी कि लड़के और लड़कियों की ग्रोथ रेट में फर्क है। पहले हम उधर से उत्तरप्रदेश से लड़कियां ब्याह कर ले आते थे इससे हरियाणा में जो लड़कियों की कमी थी वह भी पूरी हो जाती थी । मैं चाहता हूं कि अब भी ऐसी बाउंड्री बना दी जाए कि बाहर से आने वाले को लगे कि हरियाणा प्रदेश में आ गए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सरकार को माइंस की वजह से, माइंस से निकलने वाली रेता, रोड़ी, बजरी की वजह से सबसे ज्यादा आमदनी मेरे हल्के से है लेकिन वहां शिक्षा का व सड़कों का बहुत बुरा हाल है और वहां पर अनपढ़ता भी बहुत अधिक है, अनपढ़ता इसलिए है क्योंकि वहां कालेज नहीं है। लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वे अपने बच्चों को दूर पढ़ने भेज सकें। वहां बसों की भी बहुत कमी है इसलिए वहां पर बसें भी उपलब्ध कराई जाएं। मैं तो इंतजार

[चौ० अर्जन सिंह]

कर रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी और वह ही दोबारा यह उदाहरण पेश करेगी। इसके अलावा यह जो राशन कार्ड का मामला है कैटेगरी बन रही है इसमें एक समस्या और बढ़ रही है कि कैटेगरी तो बना दी लेकिन वह कैटेगरी किस ढंग से बना दी कि एक बेचारा लोन लेकर मकान बना रहा है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाता जब तक किश्त ही न उतरे तो मकान उस गरीब का कैसे हुआ? लेकिन पीले या गुलाबी राशन कार्ड बनाते समय कह दिया जाता है कि तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बन सकता क्योंकि तुम्हारा पक्का मकान है और उसमें पंखा आदि लगा हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि जब उसके मकान की लोन की किश्तें उतर जाएंगी तभी वह उसका मकान होगा। एक मेरे हल्के में जमींदारी की बहुत प्रथा है कोई आदमी कर्जा उतारने की कैपेसिटी नहीं रखता लेकिन फिर भी वह मजदूरी में कर्जा ले रहा है। वह दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा है लेकिन कर्ज नहीं उतार पा रहा है उसको जेल में मत भेजो वे बेईमान नहीं हैं लेकिन इस हालत में नहीं पहुंचे कि कर्ज उतार सकें तो मेरी आपसे अपील है कि उनकी कर्जा चुकाने की अवधि बढ़ायी जानी चाहिए। (शोर एवं विघ्न)

सुश्री शारदा राठौर (बल्लभगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के द्वारा सरकार की नीतियां और कार्यक्रम सामने आए, जो निश्चित ही प्रशंसनीय हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं कि जो बातें कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले अपने मैनीफैस्टो में कही थी, जो घोषणायें की थी घोषणा पत्र में उन्हीं घोषणाओं को जारी करने के लिए आज सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की एक झलक सामने आई। यह बहुत ही अच्छी बात है कि जिस मुद्दे पर पिछली सरकार गई और जो जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला वह था भ्रष्टाचार का मुद्दा और भय और आतंक का मुद्दा। मुख्यमंत्री जी ने उसी मुद्दे को प्राथमिकता दी है कि भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे व ट्रांसपेरैंसी रखेगें। इस अभिभाषण में भी कहा गया है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जायेगा जो निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे और भय को खत्म करने के लिए कार्य करेंगे और लॉ एण्ड आर्डर को मेनटेन रखने के लिए कार्य करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को जो इन घोषणाओं को लागू करने में सहयोग करेंगे उनको जिला स्तर पर सम्मानित किया जाये और ऐसे अधिकारियों को प्रोमोशन भी दिया जाये। ऐसे कार्यक्रम समय-समय पर और निश्चित अवधि पर चलते रहने चाहिएं ताकि इस योजना को बल मिल सके। हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले पांच साल में जितनी हत्याएं और आत्म हत्याएं हुई हैं, लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, जितनी अपहरण की घटनाएं हुई हैं। उतनी इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। इन पूरे पांच साल तक इन वारदातों के खिलाफ धरने, प्रदर्शन जलूस निकालते रहे है। पुलिस का इतना आतंक और भय था कि वहां पर धरने और प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमें दर्ज कराये गये। मुझ समेत बहुत सी महिलाओं पर मुकदमें दर्ज हुए जब कि हम शान्ति से प्रदर्शन करते थे परन्तु हम पर फिर भी मुकदमें दर्ज किए गये। बल्लभगढ़ की तिरका कालौनी में भीड़ पर लाठी चार्ज किया गया और गोलियां चलवाई गईं। मैं महिलाओं के हित के लिए महिला कमीशन गई, राष्ट्रीय महिला आयोग गई और वहां से आयोग के प्रतिनिधि ने आकर वहां पर दौरा किया और प्रशासन के खिलाफ गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी उसके बावजूद भी 16 आदमियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा मुकदमें दर्ज किए गये थे वे सरकार ने वापस नहीं लिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो बेकसूर लोग हैं और जिनके खिलाफ गलत मुकदमें बनाये गये हैं वे सभी मुकदमें वापस लिये जाये। जहां तक कृषि का सवाल है, कृषि के बारे

में बहुत से विधायकों ने बहुत सारी बातें कही हैं मैं सरकार की कृषि नीति का पूरा समर्थन करती हूं। सबसे बड़ी समस्या अनएम्पलायमैंट की है। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं तो जो हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा हमारे नौजवानों और महिलाओं का होता है, वह बेरोजगारी का होता है। यह सरकार रोजगार दिलाने के लिए कटिबद्ध है व प्रयासरत है। यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं बताना चाहूंगी कि उद्योग का इम्प्लायमैंट देने में एक अहम रोल है क्योंकि सभी को तो सरकारी नौकरी नहीं मिलती । फरीदाबाद जो कभी एशिया में उद्योग के मामले में नम्बर वन पर था। फरीदाबाद से आज उद्योग प्लायन कर रहे हैं। 1996 के बाद की सरकारों की वजह से ऐसा हुआ और वहां से उद्योग बन्द होते चले गये। व्यक्तिगत रूप से हम जब इण्डस्ट्रलिस्ट्स से बात करते हैं कि क्या वजह है कि आप फरीदाबाद से अपने उद्योगों को प्लायन कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि जो व्यापारी एक रुपया कमाता है तो उसका 75 प्रतिशत तो मुख्यमंत्री और उसके बेटे हम से *** ले जाते है और 25 प्रतिशत अधिकारी ***ले जाते हैं इसलिए हम अपने उद्योग दूसरे प्रदेशों में ले जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि फरीदाबाद में जो सिक यूनिट्स हैं जो बन्द हो गई हैं, जो बाहर चली गई हैं उसके लिए कोई इण्डस्ट्रियल डिवेल्पमैंट कमीशन बनाया जाए जो हमारे उद्योगों को बढ़ावा दें। इससे उद्योगों को स्थापित करने में काफी सहायता मिलेगी। महिलाओं और युवाओं की भी मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि महिलाओं और युवाओं का आपस में साथ है। मां के ही बेटे युवा होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं महिलाओं की जो समस्याएं हैं मुझ से पहले भी उठाई गई हैं क्योंकि आज हर गांव में 500-700 के करीब लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं चाहूंगी कि सरकार इस बारे में योजना जरूर बनाये और उसको सख्ती से लागू करे। महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने के लिए उनको कर्जा देने के लिए कानून को लचीला बनाया जाए और उनकी शिक्षा के लिए उचित प्रबन्ध किए जाएं। हमारे छात्र कल के भविष्य हैं। अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो हम अपने सुखद और खुशहाल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए PNDT Law को ज्यादा सख्त किया जाए। आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की बात भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने सामने रखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि महिलाओं को नौकरियों में भी हिस्सा दिया जाए। सरकार कोई ऐसा कानून लाए जिससे हमारी महिलाओं को नौकरियों में हिस्सा दिया जा सके। महिलाओं के लिए कर्ज के लिए भी आसान किश्तों की और कम ब्याज की योजनाएं बनाई जाएं जिससे महिलाएं लाभान्वित हो सकें। मेरे से पहले सुमिता जी ने कहा था कि महिलाओं के लिए वन विंडो सिस्टम होना चाहिए, यह बहुत सही बात है. महिलाओं में जागृति आनी चाहिए, उन्हें सही पता कि सरकार उनके लिए क्या-क्या योजनाएं लाती है। महिलाओं और युवाओं के लिए जो भी योजना लाई जाए उनके प्रसार और प्रचार में कोई कमी न छोड़ी जाए। इसके लिए जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर प्रचार और प्रसार में कोई कमी न छोड़ी जाए। वृद्धावस्था पैंशन की बात यहां आई है। आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यह पैंशन स्कीम लागू की थी, यह सही बात है। आज कई जगहों पर हमारे बुजर्ग ऐसे हैं जो पैंशन के लाभ से वंचित हैं। इस पैंशन को बांटने के लिए भी पक्षपात किया जाता है। जो लोग इसके लिए इलीजिबल नहीं हैं, जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है वे इसका लाभ उठा रहे हैं और घर में कई कई लोग इस पैंशन को ले रहे हैं और जिन्हें वास्तव में मिलनी चाहिए उन्हें नहीं मिल रही है। हम गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि बुजर्गों के पास चश्मा नहीं है वे चश्में

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[सुश्री शारदा राठौर]

पर डोरी बांधकर गुजारा कर रहे हैं। उनके चश्में का एक लैंस क्रेक है वे उसी से ही गुजारा चला रहे हैं। बुजुर्गों की स्वास्थ्य से सम्बन्धित जो योजनाएं बताई गई हैं, वे प्रशंसनीय हैं। बुजुर्गों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित जो भी उनकी जरूरतें हैं जैसे किसी को कान की मशीन चाहिए, किसी को चश्मा चाहिए, ऐसी जो भी सुविधाएं हैं वे सभी सीनियर सिटीजन्स को दी जानी चाहिएं।

श्री अध्यक्ष : आप वाइंड अप करें।

सुश्री शारदा राठौर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बात और कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। एजुकेशन के बारे में अभी महेन्द्र प्रताप जी ने बताया कि फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कैम्पस या ब्रांच बनाई जाए क्योंकि फरीदाबाद काफी रवैन्यू देने वाला जिला है और फरीदाबाद हरियाणा का कमाऊँ पूत है। हमें एजूकेशन से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। बल्लभगढ़ विधान सभा क्षेत्र के मोटूका गांव में 89 एकड़ जमीन पिछली सरकार ने एक्वायर की थी ताकि वहां जेल बनाई जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी उसका उद्घाटन नहीं कर पाए, शायद इसमें भी कोई अच्छाई छुपी होगी। उनका इरादा मुझे पता नहीं लेकिन लोग कहते हैं कि उन्हें किसी इंडस्ट्रिलिस्ट ने कोई और योजना बता दी थी तो उन्होंने अपना इरादा उसी वक्त कैंसिल कर दिया। इस सरकार में शायद वहां कोई अच्छा काम उस जमीन पर हो जाए। वह 89 एकड़ जमीन अभी खाली पड़ी है और उस पर कुछ नहीं बना। मैं चाहूंगी कि वहां पर कोई एजुकेशन इंस्टीच्यूट सरकार लेकर आए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक बात और कहना चाहूंगी कि अब आगे गर्मी का मौसम आने वाला है। सरकार द्वारा प्रदेश में बिजली और पानी को प्राथमिकता देनी चाहिए। फरीदाबाद नगर निगम को सम्भालने के लिए पहले कमिशनर हुआ करता था लेकिन पिछले मुख्यमंत्री महोदय ने यह काम उपायुक्त को दे दिया था जिससे हमारे नगर निगम का काम सफर करता है। मैं चाहूंगी कि वहां पर फिर से कमिशनर को लगा दिया जाए ताकि फरीदाबाद नगर निगम का काम सुचारू रूप से चल सके। चूंगी को फिर से चालू किया जाए ताकि नगर निगम की इन्कम हो सके। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जमीन का जो कलैक्टर रेट बढ़ा हुआ है उसको भी कम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया।

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister, will give reply.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिया और हमारे वरिष्ठ साथी चौधरी शमशेर सिंह जी ने उनका धन्यवाद करने का जो प्रस्ताव रखा है इससे पहले कि मैं उस पर चर्चा करूं मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि आज विश्व जल दिवस है। मैं विश्व जल दिवस के बारे चर्चा करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सभी को मालूम है कि जल ही जीवन है। पानी की समस्या आज हम सबके सामने बहुत अहम समस्या बनी हुई है। आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यह समस्या और अधिक गहरा सकती है तथा विकराल रूप ले सकती है। अध्यक्ष महोदय, जैसे आज यह आम चर्चा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह पानी के लिए होगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है और हम सबका यह प्रथम कर्तव्य है कि हम सब जल संरक्षण का हर संभव प्रयास करें ताकि इस संकट से हम बाहर निकल सकें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आना चाहूंगा। चुनावों में हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी को शासन सौंपा है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी 120 साल पुरानी पार्टी है और लोगों ने बहुत ही आशा और उम्मीदों से कांग्रेस पार्टी को यह शासन सौंपा है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास त्याग, कुर्बानियों और स्वतंत्रता संग्राम से लिखा हुआ है। इसमें महात्मा गांधी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जी के जो सपने थे वे आज श्रीमती सोनिया गांधी जी के कुशल नेतृत्व में साकार होंगे। मैं यही विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे जो महान नेता रहे हैं। उनके सपनों को साकार करने में किसी प्रकार की कोई कसर हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी। यानि हम अपने महान नेताओं के सपने पूरे करने के पुरजोर प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने हरियाणा के नव-निर्माण की आज जो परिकल्पना की है, उन्होंने इसे ब्रोड बेस्ड थ्रस्ट बताया है। इस पूर्ण रूप से नीति की घोषणा तो आने वाले समय में करेंगे। जिन चीजों की चर्चा मेरे साथियों ने की है मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी के सहयोग से समृद्ध, सुदृढ़ता, स्वस्थ्य, शिक्षित और सुरक्षित समाज का सुन्दर हरियाणा अब बनकर ही रहेगा। मैं कल्पना में विश्वास नहीं रखता। मैं ठोस परिणामों में विश्वास रखता हूं और जो बातें मैंने कही हैं परिणामों से उनको आंका जाएगा। हरियाणा की जनता ने जिन आशाओं और उम्मीदों से हमें यह जिम्मेवारी दी है इस पर हम खरे उतरेंगे। We are here not to rule but to serve the people of Haryana. त्यागमूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी जी के ओजस्वी नेतृत्व और कुशल नेतृत्व में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो जिस जगह भी वे हरियाणा में आई और इस देश के प्रधानमंत्री जी जहां पर भी विधान सभा चुनावों में आये थे तो उन्होने विश्वास दिलाया था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन देंगे। जब यह बागडोर कांग्रेस पार्टी ने संभाली और थोड़े दिन के शासन के बाद जो हमारा तजुर्बा हुआ, मैं किसी की निंदा करने का आदी नहीं लेकिन जहां पर भी देखा और गहराई से सोचा कि हमारे प्रदेश का बहुत बुरा हाल हुआ है। सभी साथियों ने भी इस बारे में चर्चा की और कांग्रेस पार्टी ने पिछली सरकार के कार्यों की एक चार्जशीट भी राज्यपाल जी को दी थी इस बात की चर्चा चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने भी की कि किस-किस तरह के घोटाले पिछली सरकार के समय में हुए, यह बात किसी से छिपी नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता को इस बारे में मालूम है। अध्यक्ष महोदय, पिछले लोक सभा के चुनावों में हरियाणा की जनता ने चौटाला साहब की सरकार को संदेश दिया था लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली और लोक सभा के चुनावों के बाद से लेकर विधान सभा के चुनावों के बीच में उन्होंने जो निर्णय लिये हैं उनसे हरियाणा का बहुत अहित हुआ है। उन्होंने जो फैसले इस दौरान लिये ऐसे फैसले किसी भी प्रजातांत्रिक प्रदेश के इतिहास में देखने को नहीं मिलेंगे। इस दौरान जिन संस्थाओं पर हमारा भविष्य निर्भर है उनके बारे में पिछली सरकार ने क्या-क्या फैसले लिये इस बारे में सबको जानकारी है। किस तरह से समय से पहले ही एच०पी०एस०सी० के मैंबरों के इस्तीफे दिलवाकर नये मैंबर रातों-रात बनाये ताकि आने वाले 6 साल तक वे उस पद पर रह सकें और वे अपनी मनमानी कर सकें, ये बातें किसी से छिपी नहीं हैं। स्पीकर साहब, पिछली सरकार द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्य किए गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी ने जो अपना अभिभाषण दिया है उसमें सरकार की एक एक ब्रोड बेस्ड दिशा दर्शायी गई है। हमारी मौजूदा सरकार नई दिशा और नई गति व नव निर्माण हरियाणा में देने के लिए वचनबद्ध है। हरियाणा में हर नागरिक को मान-सम्मान दिया जाएगा और उनकी भावनाओं की रक्षा

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

की जाएगी। सभी प्रकार की संस्थाओं के गर्व और गरिमा को बहाल किया जायेगा चाहे वह शयन की संस्था है या नौकरियों की संस्था है और चाहे लेजिस्लेचर है। कहने का मतलब यह है कि चाहे पंचायती राज की संस्था है या कोई और संस्था है, सबका मान सम्मान बहाल किया जायेगा। पंचायती राज के बारे में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने जो घोषणा की थी उसके बारे में वे जो अमैंडमैंट लेकर आये थे उन्होंने उसे पास भी करवाया था । स्वर्गीय महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज का जो सपना था उसे पूरा करने का राजीव जी ने इस अमैंडमैंट के जरिये प्रयास किया था। पिछली सरकार ने किस प्रकार से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों के हितों से खिलवाड़ किया वह सभी को पता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कार्य पंचायतों का था उस कार्य को भी करने के लिए मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते थे । उन्होंने विकास समितियां बना दी। जो पंचायतें लोगों ने चुन करके भेजी थी वे डिफैक्ट कर दी गई। चाहे वे पंचायतें हैं, चाहे पंचायत समितियां हैं और चाहे जिला परिषदें हैं। हमारी सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध भी है कि जो ऐसी सभी संस्थाएं हैं उनकी गरिमा और उनकी क्रैडिबिलिटी कायम की जाए। अब पूरे प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं। लोगों की मन्शा से पंचायतें चुनी जाएंगी और अपने अपने कार्य क्षेत्र में वे संस्थाएं पूर्ण स्वतंत्र होंगी। इसमें किसी प्रकार का कोई दखल सरकार की तरफ से नहीं होगा। मैं पावर पोलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता। मैं राजनीति में हूं और मेरे लिए राजनीति सेवा का एक माध्यम है। मुझे विपक्ष में रहते हुए पिछली सरकार का जो तजुर्बा हुआ है उससे तो यही लगता है राजनीति में जो भी आता है वह चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ते वक्त वह यही कहता है कि मैं जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। पिछले 2000 के चुनावों में लोग एक नई सरकार इस उम्मीद से यहां पर ले करके आये थे कि वह सरकार प्रदेश का भला करेगी लेकिन सिद्ध यह हुआ कि वे लोग जनसेवा का नाम लेकर सत्ता में आ गए तो फिर वे जनसेवा की बजाय स्वयंसेवा में लग गए। अध्यक्ष महोदय, मैं हाऊस को यकीन दिलाता हूं कि इस सरकार में पहले की सरकार की तरह ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं तो पोलिटिक्स ऑफ डिवैल्पमेंट में यकीन रखता हूं। मेरे साथियों का भी इसमें यकीन है। विकास की पहली आवश्यकता किसी भी प्रदेश की हो उसके लिए जरूरी है कि वहां पर शांति और सुरक्षा लोगों को मिले। यहां पर जैसा राज्यपाल महोदय ने दर्शाया है और बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो कभी भी शांति कायम नहीं हो सकती। यह सब तभी संभव होगा जब प्रदेश से भ्रष्टाचार का सफाया हो। यह निश्चित है कि भ्रष्टाचार और गरीबी दोनों सगे भाई बहन हैं। जहां पर भ्रष्टाचार होगा वहां पर गरीबी का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। सरकार की कोई भी नीति हो और कितना भी पैसा आता हो, वह नीचे तक नहीं पहुंचता । भ्रष्टाचार के बारे में राजीव गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि अगर ऊपर से एक रुपया चलता है तो नीचे तक सिर्फ 10 पैसे पहुंचते हैं। यहां का अगर इतिहास खोल कर देखें तो कोई यकीन नहीं करेगा कि उस समय किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग हुआ था। हम गलत कामों की समीक्षा करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में और मेरे बहुत सारे माननीय साथियों ने सरकारी ऑफिसर्ज और राजनेताओं की भी बात कही है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि हमारी नीति रिवार्ड और पनिशमैंट की होगी। जो भी अधिकारी अच्छा काम करेंगे और जनहित के काम करेंगे उनको पूरा मान-सम्मान मिलेगा और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा लेकिन अगर कोई अधिकारी

किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार करेगा या भ्रष्टाचार की बात करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं)** सजा के जो तरीके बने हुए हैं उनके मुताबिक सजा दी जाएगी केवल बदली करना कोई सजा नहीं होगी बल्कि दूसरी तरह की सजा भी उसमें होगी । अध्यक्ष महोदय, यहां पर सारे क्षेत्रों की बातें आईं। हमारे साथी रणबीर सिंह जी ने कहा स्पोर्टस के मामले में यहां पर कोई चर्चा नहीं हुई । मैं हाऊस की जानकारी के लिए यह कहना चाहूंगा कि जल्दी ही हम इसके बारे में पूरी पॉलिसी लाएंगे जिसमें खेल-कूद की सारी बातें होंगी। महिला सशक्तिकरण हो या दलित भाईयों के लिए राहत की बात हो, सब के लिए अलग-अलग से कार्यक्रम होंगे क्योंकि अगर प्रदेश को अच्छा साबित करना है तो हमें यह सब करना होगा। जैसे कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि हम एक ही लक्ष्य लेकर चले हैं कि आने वाले चुनाव तक हरियाणा पूरे देश का नम्बर एक प्रदेश होगा। प्रदेश को नम्बर वन बनाने के लिए हमें प्रदेश का चहुंमुखी विकास करना चाहिए। वह विकास चाहे स्पोर्टस का हो या किसी और चीज का हो हम सब करेंगे। चहुंमुखी विकास ही एक रास्ता है जो प्रदेश को आगे ले जा सकता है। विकास की गंगा सारे प्रदेश में बहे इसके लिए हम सब को मिलकर काम करना होगा और हम इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। शायद यही कारण है कि आज से करीब डेढ़ साल पहले गंगा मैया ने मुझे जीवनदान दिया है। अध्यक्ष महोदय, बाकी का जो जीवन है बगैर किसी कुर्सी के लालच के मैं वह जीवन हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा में लगाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। जहां तक किसान का सवाल है, पिछली सरकार अपने आप को किसानों की हितैषी सरकार कहती थी लेकिन किसानों की जो दुर्दशा उस सरकार ने की थी वह सब को मालूम है। जैसे किसानों के साथ खून की होली उस सरकार के समय में खेली गई थी, हरियाणा के इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। मैं खुद और मेरे साथी कण्डेला और गुलकनी गावों में मौके पर गए थे और किसानों की हालत को देखा है। सरकार के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन हुआ करते हैं, प्रजातन्त्र में सभी लोगों को अपनी मांग रखने का अधिकार है और उसका तरीका भी है लेकिन किस प्रकार से खेतों में खड़े लोगों को गोलियां से भूना गया लोग उसे भूले नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता । अंग्रेजों के राज में तो हमने सुना था कि लोगों पर देशद्रोह के मुकदमें दर्ज होते थे लेकिन हिन्दुस्तान में हमने केवल हरियाणा में ही सुना है कि जो लोग किसानों के हित की बात उठाते हैं उन पर देशद्रोह के मुकदमें बनाए गए। घासी राम जैसे नेताओं पर सरकार ने कई केसिज बनाए। हमारी सरकार ने कैबिनेट में यह फैसला किया है कि इस किस्म के जितने भी मुकदमें बनाए गए हैं वे वापिस लिए जाएंगे। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं)** अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने पहले फरवरी के मास में हुई हेलस्टॉर्म और अब फिर हेलस्टॉर्म पड़ने की चर्चा की। इस ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुक्सान की बात आई और कुछ साथियों ने कहा कि मुआवजे के रूप में जो राशि एनाउंस की गई है वह काफी कम है। फरवरी के महीने में किसानों की फसलों का काफी नुक्सान हुआ है और अब फिर ओलावृष्टि के कारण हमारे प्रदेश के किसानों का भारी नुकसान हुआ है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कम्पनसेशन एमाउंट है वह इनपुट कॉस्ट से रिलेटिड है यानि जितनी लागत है उससे रिलेटिड है। जिन फसलों को नुकसान हुआ है उनमें गेहूं की भी एक फसल है, चना और दूसरी फसलें भी हैं। लेकिन गेहूं की जो फसल है उसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट सबसे ज्यादा है इसलिए हमने फैसला किया है कि फरवरी में सरकार ने एक हजार रुपये पर एकड़ का जो मुआवजा घोषित किया था उसे

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

बढ़ाया जाए। जिस किसान का नुक्सान 26 से 50 प्रतिशत तक हुआ है उसके बारे में हमने फैसला लिया है कि हम उसको मुआवजा एक हजार रुपए प्रति एकड़ की बजाय डेढ़ हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे। इसके अलावा और दूसरी फसलें हैं हमने उनके मुआवजे में 25 प्रतिशत का इजाफा किया है। स्पीकर सर, जहां पर 75 प्रतिशत नुक्सान हुआ है वहां पर हमने फैसला लिया है कि दो हजार रुपए प्रति एकड़ की बजाय तीन हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे। सदन में कृषि के विविधिकरण के बारे में चर्चा हुई है। मैं पिछली सरकार के वक्त में अपोजिशन में बैठता था और श्री ओम प्रकाश चौटाला जी यहां पर मेरी जगह पर बैठा करते थे और वे बार बार यह कहते थे कि किसानों को फूल पैदा करने चाहिएं। यह ठीक है कि फसलों का सर्कल चलते रहना चाहिए ताकि भूमि उपजाऊ रहे। एक फसल की खेती करते रहने से जमीन की स्ट्रैंथनिंग कम हो जाती है। आज किसानों की होल्डिंग कम हो गई है। अगर किसान की आमदनी बढ़ानी है तो हमें फसलों का विविधिकरण करना होगा और कहीं पर फ्रूट्स और कहीं पर सब्जियों को लगाना होगा। आज हमें कृषि के सर्कल को बदलना होगा। अगर ऐसा होगा तो किसानों को फायदा होगा। लेकिन उससे पहले हम किसानों को दूसरी तरफ लेकर जाएं, तो हमें उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर जुटाना होगा। हमें किसान की फसलों के लिए मार्किटिंग का प्रबन्ध करना होगा। अगर मार्किटिंग नहीं होगी तो उसकी सारी की सारी पैदावार सड़ जाएगी। स्पीकर सर, इस तरह के इन्फ्रास्ट्रक्चर की जो बात हमने कही है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्पीकर सर, पशुपालन और डेयरी फार्मिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा क्योंकि यही वे दूसरे धन्धे हैं जिनको किसान आसानी से कर सकता है। स्पीकर सर, सदन में मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि दुनिया में गायों और भैंसों की बढ़िया नस्ल को देखने के बारे में एक लेटैस्ट रिसर्च की गई है। उस रिसर्च में दुनिया भर से गायों और भैंसों को शामिल किया गया था और उस रिसर्च में हरियाणा की गायों और भैंसों को अव्वल नम्बर का पाया गया है। स्पीकर सर, गांवों में फलों और सब्जियों की स्टोरेज होनी चाहिए। जब तक इस फैसिलिटी को देने के पूरे प्रयास नहीं किए जाएंगे तब तक गांव वालों को फायदा नहीं हो पाएगा। स्पीकर सर, इसके अलावा सदन में पानी के न्यायोचित बंटवारे के बारे में चर्चा की गई है। हमारे सदन के एक सदस्य सीता राम जी, जो कि पिछली सरकार के वक्त में भी हमारे साथ सदन में थे, ने बोलते हुए कहा कि यह पानी उत्तरी हरियाणा में जाएगा या नहीं जाएगा। मैं इनको यह कहना चाहूंगा कि हमने न्यायोचित पानी के बंटवारे की बात की है। जिसका जितना हक है उसको उतना हक मिलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज तक हरियाणा में पानी के बंटवारे में इन्साफ नहीं हुआ है, न्यायोचित बंटवारा नहीं हुआ है। मेरे पास सारा इतिहास है और उस बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। हमारे बलदेव सिंह जी भी मंत्री रहे हैं और दूसरे साथियों को भी ज्ञान है और जिनके-जिनके शासन रहे हैं उनको भी यह ज्ञान था। स्पीकर सर, जब से हरियाणा बना है तब से हरियाणा में पानी का बंटवारा न्यायोचित ढंग से नहीं हुआ है। ब्यास का जो पानी है वह 1977 में पहली दफा हरियाणा की भूमि को टच हुआ था, तब चौधरी देवी लाल जी मुख्यमंत्री थे और तब से ही पानी के बंटवारे में **** का काम शुरू हुआ था। आज वे भगवान को प्यारे हो गए हैं। मैं उनकी सदैव इज्जत करता रहा हूं। वे स्वतन्त्रता सेनानी थे और मेरे पिता जी के साथ थे लेकिन हकीकत तो हकीकत है। मैं आज आप सभी के सहयोग से मुख्यमंत्री हूं। चाहे हरियाणा में कोई भी मुख्यमंत्री हो और जो भी मुख्यमंत्री होता है वह

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से एक्सपंज कर दिये गए।

प्रदेश का हैड होता है, वह एक परिवार में बाप की तरह होता है। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर एक बाप के चार बेटे हैं और उस बाप के पास चार रोटियां हैं, अगर वह बाप चारों बेटों में एक एक रोटी बांट देगा, चाहे बच्चे भूखे ही रहे, समाज यह कहेगा कि बाप ने बच्चों के साथ इन्साफ किया है। लेकिन एक बाप के चार बेटे हैं और उस बाप के पास चार रोटियां हैं, अगर वह बाप तीन रोटियां एक बेटे को दे दे और एक रोटी तीन बेटों में बांट दे तो कौन सा समाज यह कहेगा कि यह न्याय किया है लेकिन ऐसा अन्याय हरियाणा में होता रहा है। हमारे सिंचाई मंत्री ने भी इस बात की चर्चा की है और यही बात सोचकर कि जिस इलाके के साथ सबसे ज्यादा अन्याय होता रहा है उसी इलाके के अपने साथी को हमने सिंचाई विभाग दिया है, यह जिम्मेदारी दी है ताकि वे अपना काम मेहनत से कर सकें। अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए सारा हरियाणा बराबर है लेकिन जिसका जो हक है वह उसको जरूर मिले। मैं समझता हूं कि जो भी हरियाणा का हित समझता है वह इस बात से जरूर सहमत होगा कि सभी जिलों को बराबर पानी मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जल संरक्षण के बारे में बहुत बातें यहां पर की गयी । आप जी०टी० रोड पर देखें। करनाल की भूमि या कुरुक्षेत्र की भूमि जोकि बहुत उपजाऊ है, सोना उगा रही है लेकिन जिस स्पीड से वाटर लैवल नीचे जा रहा है उसको देखते हुए आज से दस साल बाद वहां कुछ होने वाला नहीं है इसलिए आज से ही वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे और वह कदम हम उठाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से यहां पर हमारे साथी ने एस०वाई०एल०की चर्चा की। एस०वाई०एल०पर चर्चा कई बार यहां पर ओम प्रकाश चौटाला भी करते थे। हमने उस वक्त इस बारे में प्रस्ताव भी पास किए। अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी चर्चा हुई कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है और केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार है तो मैं कहना चाहूंगा कि जो एस०वाई०एल०का इतिहास जानता है, हरियाणा का इतिहास जानता है उसको यह मालूम होना चाहिए कि एस०वाई०एल०की शुरुआत कहां से हुई। एस०वाई०एल०के निर्माण के लिए सबसे पहले उद्घाटन कस्सी मारकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। उस समय वे केन्द्र में प्रधानमंत्री थीं। इस बारे में जो फैसले हुए चाहे वह राजीव-लोंगोवाल समझौता हो वह भी राजीव जी के समय में ही हुआ। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के समय में भी यह मुद्दा उठाया गया और यह भी सही है कि हरियाणा में इस मुद्दे पर कई सरकारें बनी हैं और कई सरकारें गिरी भी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें यह सोचना पड़ेगा कि हरियाणा में अब तक अगर एस०वाई०एल०नहीं बनी है और इसमें इतना विलम्ब हुआ है तो इसके लिए दोषी कौन है ? अध्यक्ष महोदय, यह बात अब सिद्ध हो गयी है, कैसे सिद्ध हो गयी है वह मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हित में फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसका आधार क्या माना है,सुप्रीम कोर्ट ने उसका आधार माना है राजीव लौंगोवाल समझौता और राजीव लौंगोवाल समझौते का विरोध किसने किया है ? अध्यक्ष महोदय, इतिहास साक्षी है, हरियाणा के लोग साक्षी हैं कि उसका विरोध उस समय लोकदल ने किया । पता नहीं उनकी पार्टी का उस समय क्या नाम था लेकिन चौधरी देवीलाल जी उसके अध्यक्ष थे। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी इस समझौते का विरोध किया है। जो आज चर्चा कर रहे हैं यह तो सबके सामने है। न्याय युद्ध का नाम लेकर यहां पर उसका विरोध किया गया।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में कुछ कहना है।

Shri Bhupinder Singh Hooda : I am not yielding. इंदौरा साहब, आप तो पार्लियामैंट में रहे हैं कोई नये सदस्य नहीं हैं।

Mr. Speaker : Take your seat Mr. Indora Ji. That is not the way.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह विरोध किसने किया है? इसमें जो इतना विलम्ब हुआ है वह किसकी वजह से हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस समय यहां पर चौटाला साहब की सरकार थी और केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हरियाणा के हक में लेकिन उसके बाद मैं 1.5 साल तक यह फैसला ठंडे बस्ते में रहा। उस समय न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ किया और न ही चौटाला साहब की सरकार ने कुछ किया जबकि असैम्बली ने इसके लिए उनको अधिकृत किया था। मैंने खुद उधर खड़े होकर कहा था कि आप इस बारे में कदम उठाओ जहां पर भी आप कहेंगे हम चलेंगे पूरा सहयोग देंगे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर साथ देंगे लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। 1.5 साल तक वह फैसला लटका रहा। अध्यक्ष महोदय, आज ये कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बनी उसी दिन हम उनसे मिले। अध्यक्ष महोदय, उस दिन भी मैं सांसद था और जब तक मैं इस्तीफा नहीं देता तब तक मैं सांसद हूं बाकी आपकी दया से मैं यहां पर हूं। मेरे अलावा और भी कांग्रेस के 9 सांसद थे। जिस दिन सरकार बनी उसके थोड़े ही दिन बाद हम वहां केन्द्र सरकार में मिले और जो डेढ़ साल तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठंडे बस्ते में रखा था, उसका उस समय केन्द्र सरकार ने फैसला किया कि जो एस०वाई०एल० का बकाया निर्माण किया है वह सी०पी०डब्ल्यू०डी० करेगी, पंजाब सरकार नहीं करेगी। यह काम केन्द्र में जब बी०जे०पी० की सरकार थी उन्होंने भी नहीं किया। पंजाब की असैम्बली में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं वहां एक गैर कानूनी ऐक्ट पंजाब की सरकार ने पास किया और जो जल समझौता था, उसको निरस्त करने का काम किया। फिर हम सारे सांसद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिले और श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिले। सुबह हम मिले और उसी शाम को कैबिनेट की मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि रैफरैंस के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास केस भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो केस पड़ा है वह क्या है ? सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने जो गैर कानूनी और गैर इखलाकी ऐक्ट पास किया है उसका रैफरैंस है। सुप्रीम कोर्ट ने नहर के निर्माण के बारे में तो फैसला हमारे हक में कर ही रखा है। अभी दो दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि पंजाब के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि जो जल विवाद है उसके लिए हम बातचीत करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि बातचीत की गुंजाइश ही कहां है ?. जो गलत कानून पंजाब ने पास किया है उसको निरस्त करो, उसको निरस्त किए बगैर हरियाणा कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। यह हमारे लिए जीवन रेखा का प्रश्न है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष के साथियों से भी हमें पूरा सहयोग मिलेगा। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बारे में तथ्य की बात बताई है। सबको मालूम है कि यह नहर हरियाणा की जीवन रेखा है विलंब क्यों हुआ है मैं इसके पिछले इतिहास में जाना नहीं चाहता। हम सब मिलकर हरियाणा के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। ओम प्रकाश चौटाला ने तो इराडी कमीशन को भी काले झण्डे दिखाये थे जिन्होंने हमारे हक में समझौता किया था। (Interruptions) I am not yielding. I have gone through the facts.

Dr. Sushil Indora : If you are not yielding, why should I intervene ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में है। रैफरैंस का भी जल्दी फैसला होगा और हम अपना हक लेकर रहेंगे। इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा

कि अगर हम पंजाब को कह रहे हैं कि वह हमारे हक का पानी नहीं दे रहा है तो हमें भी उस कसौटी पर खरा उतरना चाहिए कि हरियाणा द्वारा जिन राज्यों को पानी का हिस्सा दिया जाना बनता है वह हरियाणा को भी देना चाहिए। हम पंजाब को अपना बड़ा भाई कहते हैं और कहते हैं कि पानी का हमारा हक है और वह उसे हमें देना चाहिए। बिजली की बात हुई । बिजली का बहुत ही इम्पोर्टेंट सैक्टर है। बिजली के बगैर विकास की बात नहीं सोची जाती इसलिए किसानों के बिजली के बिलों की बात हुई। एक-एक किसान पर इतना बोझ लगा दिया है कि वह अपनी सारी जमीन गिरवी रख दे और उसके बच्चे भी सारी उम्र कमाते रहें तो भी वह कर्जा नहीं उतार सकता। बिजली के लिए पॉवर सैक्टर का और स्वास्थ्य के लिए उसकी आमदनी का बढ़ना बहुत जरूरी है। आज सबको यदि बिजली देनी है तो उसके लिए यह जरूरी है कि ट्रांसमीशन लौसिज कम हों। हरियाणा में मेरे ख्याल में 40-44 प्रतिशत के करीब ट्रांसमीशन लौसिज हैं जबकि पंजाब में 17या 18 परसैंट लाइन लौसिज हैं। आज हमें ट्रांसमीशन लौसिज और चोरी कम करने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। इन लौसिज को कम करने के बारे में सुरजेवाला जी ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। हमारी कोशिश होगी कि प्रदेश में कैप्टिव पॉवर स्टेशन हों। पुराने बिजली के बिलों की सैटलमैंट हो सके उसके लिए हमने कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों की एक पांच 17.00 बजे मैंबरों की समिति बनाई है। जो जल्दी ही अपना कार्य शुरू करेगी और इन चीजों का निपटारा करेगी। वित्त मंत्री जी उस कमेटी को हैड कर रहे हैं, एक्साईज एण्ड टैक्सेशन मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, इरीगेशन मिनिस्टर यानी 5 वरिष्ठ मंत्री इस कमेटी के सदस्य हैं जो इस बात का निपटारा करेंगे ताकि हमारे यहां पूरी बिजली हो और सस्ती बिजली हो। अभी उदयभान जी ने फरीदाबाद की चर्चा की कि फरीदाबाद का एन०टी०पी०सी० का प्लांट है उसकी क्षमता 432 मैगावाट है। उन्होंने कहा कि उस प्लांट से हरियाणा को पूरी बिजली नहीं मिल रही है। उसका कारण है, वहां जो प्लांट एन०टी०पी०सी० ने लगाया था वह सी०एन०जी० के नाम से लगाया था और जो सी०एन०जी० से बिजली पैदा होती है उस प्लांट में वह हरियाणा को 1.90 या 2.20 रुपये के भाव से मिलती है। जितनी उस प्लांट की कैपेसिटी है उस हिसाब से हमें 75 प्रतिशत बिजली मिल रही है। बकाया जो 25 प्रतिशत बिजली है वह हम नाथपा से प्राप्त कर रहे हैं जिसका भाव 4.00 रुपये प्रति यूनिट है। सवाल यह है कि हम इतनी मंहगी बिजली क्यों लें ? क्योंकि गैस की सप्लाई पूरी नहीं है इसलिए हमें महंगी बिजली बाहर से लेनी पड़ रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि हरियाणा की बिजली की कमी पूरी हो गई है या हम अपने हिस्से की पूरी बिजली नहीं ले रहे हैं। इसके बहुत से कारण हैं और एक लम्बी बात है। यहां पर बिजली का पूरा उत्पादन हो, ट्रांसमिशन लौस कम हो, पूरी बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले और यह जब तक नहीं होगा तब तक हरियाणा पूरा विकास नहीं कर सकता है। हम इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस बारे में कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी तो फिर उसको अमली जामा पहनाया जायेगा। मैं अब तीसरा स्वास्थ्य की बात करता हूं। सबको मालूम है कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। लेकिन खासतौर से गांव के गरीब आदमी को सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। पिछली सरकार के समय में पर्ची की बात थी हम इसे एग्जामिन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बैठी हैं। पिछली सरकार की यह बात मुझे बहुत अखरती है कि पोस्टमार्टम के लिए भी 120 रुपये लिए जाते थे वह आज से ही खत्म किए जा रहे हैं। अब पोस्टमार्टम पर कोई पैसा नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति मर जाये और उसके परिजनों को ऊपर से फीस भी देनी पड़े। गरीब आदमी यह फीस कहां से देगा। हम कोशिश करेंगे कि नीचे तक यानी देहात तक स्वास्थ्य सेवायें जायें। श्री नरेश यादव जो अटेली से जीत कर आये हैं। एक अजीब बात

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

उन्होंने बताई कि वहां के अस्पताल की एक्स रे की मशीन रिपेयर के लिए गई थी और वह अब तक वापिस नहीं पहुंची है। मैं नरेश जी को बताना चाहूंगा कि एक हफ्ते तक अस्पताल में एक्स रे मशीन पहुंच जायेगी। जो बात हमारे घोषणा पत्र में भी नहीं है मैं भी ऐसी बात नहीं कहूंगा, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जो बात संभव होगी वहीं जुबान से कही जायेगी। हम सब चीजों पर विचार करेंगे। महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। पीने के पानी के लिए विशेष तौर से दक्षिणी हरियाणा में जहां पीने का पानी भी नहीं है स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। गांव में शहरी सुख सुविधा देने का हमारा पूरा प्रयास होगा। क्योंकि गांव से शहरों की तरफ प्लायन रोकने के लिए गांवों में शहरी सुविधाएं देनी पड़ेगी। जहां तक इण्डस्ट्रीज की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि वह गांवों में सामाजिक बुराई के रूप में तब्दील होती जा रही है। खाली भूख से ही नहीं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए साधन उपलब्ध कराये जायें। यह प्राथमिकता इस सरकार की रहेगी उसके लिए अन्तर और ज्यादा न बढ़े इसलिए यह आवश्यक है कि यहां राज्य में औद्योगिकीकरण हो। एक ऐसा माहौल प्रदेश में बनाना पड़ेगा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। जो अच्छे उद्योग पिछले पांच साल में प्रदेश को छोड़ने की बात कर रहे थे, जैसे कानून और व्यवस्था की बात है, भ्रष्टाचार की बात है भ्रष्टाचार को खत्म किया जायेगा और कानून व्यवस्था में सुधार होगा। शान्ति का प्रयास होगा तभी कोई बाहर से आकर उद्योग लगायेंगे क्योंकि ग्लोबलाईजेशन और लिब्रलाईजेशन का जमाना है उसका फायदा हरियाणा प्रदेश को बहुत मिल सकता है क्योंकि हम दिल्ली के तीन तरफ हैं और हम पूरी फैसीलिटीज उनको देंगे We shall facilitate and not control the investments जो लोग बाहर से हमारे यहां इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आएंगें उनको पूरी फैसीलिटीज देंगे, हम उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, हम उन पर अपनी बात नहीं थोपेंगे कि आप यह कर दो वह कर दो। जब हम उन पर अपनी बात न थोपने का माहौल बनाएंगें तभी कोई उद्योगपति अपना उद्योग लगाने के लिए हरियाणा में आएगा। सोशल वैल्फेयर के बारे में यहां चर्चा हुई। हमारी बहन जी ने जवाब दिया कि ओल्ड ऐज पैंशन देना हमारी जिम्मेवारी है और ओल्ड ऐज पैंशन कांग्रेस पार्टी की नीति है। इंदिरा गांधी जी ने इस नीति को सोचा था लेकिन पैंशन के बारे में बहुत सी शिकायतें हैं कि जिसको मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रही है और जिसको नहीं मिलनी चाहिए उसको मिल रही है। इसकी पूरी छानबीन होगी और सही आदमियों को पैंशन दी जाएगी। जब पैंशन की जरूरत होती है तब नहीं मिलती सरकार इस बात का भी पूरा प्रबंध करेगी कि पैंशन हर महीने की 7 तारीख को मिल जाए ताकि वह पैसा उसके काम आ सके। मैं और मेरे साथियों ने यह फैसला किया है। आज से 75 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने डांडी यात्रा साबरमती से लेकर डांडी तक की थी। हमने भी अभी 18 तारीख को डांडी यात्रा की जिसकी शुरूआत श्रीमती सोनियां गांधी करके आई थी। 75 साल पहले यह घटना हिन्दुस्तान में हुई थी जिसमें एक नमक की चुटकी ने पूरे देश में एक लहर फैलाई और एक चेतना जगाई जिसका नतीजा हमें आजादी के रूप में मिला। सोनिया गांधी ने 75 साल के बाद पुन: डांडी यात्रा की शुरूआत की और मुझे भी अपने साथियों के साथ इस यात्रा में 18 तारीख को शामिल होने का मौका मिला। गांधी जी का सपना साकार हो, इस वास्ते मैंने और मेरे कहने पर मेरे साथियों ने यह फैसला किया है कि हम कोई भी फैसला करने से पहले गांधी जी जो कहकर गए थे उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगें। गांधी जी ने कहा कि कोई फैसला करने से पहले उस व्यक्ति की तस्वीर जो उस प्रदेश का सबसे गरीब आदमी हो और उसको उस फैसले से क्या लाभ हानि पहुंचने वाला है का चेहरा

देखकर फैसला लें। हम हरियाणा में व्यवस्था ऐसी करेंगें कि सामाजिक सीढ़ी में जो अन्तिम पांव सीढ़ी पर खड़ा है उसको लाभ हो ताकि गरीब आदमी का जीवन स्तर ठीक हो सके। जो पैसे वाले हैं। जिसका अच्छा स्तर है वे यहां नहीं रहेंगें वे तो दिल्ली चले जाएंगें या अन्य शहरों में चले जाएंगें। हम चाहेंगें कि गांव और शहर के गरीब आदमी का जीवन स्तर अच्छा हो। हमारी सरकार चाहती है कि लोगों की हर फैसले में भागीदारी हो। सरकार बदल जाने के बाद भी कार्य होते रहने चाहिएं, सिर्फ चेहरे बदलने से काम नहीं रूकने चाहिएं। हम पुरानी व्यवस्था को बदलेंगें और उस व्यवस्था से भ्रष्टाचार और भय को निकालकर उखाड़ फैंकेंगें। यह बात केवल राजनेताओं पर ही लागू नहीं होगी बल्कि निचले लैवल तक लागू होगी। मैं आज सभी को चेतावनी दे रहा हूं और आज मुझे चेतावनी देने का मौका मिला है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो भी हो चाहे वह तहसील हों, चाहे वह थाना हो या कोई और जगह है जो प्रथाएं, व्यवस्था उनमें काम करने की बनी हुई हैं, वे अपना काम ठीक प्रकार से करें और वे मुख्य धारा में आ जाएं। अगर कोई पकड़ा गया तो उसे नहीं बक्शा जाएगा। पिछली सरकार के समय कोई गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करने के लिए जमीन बेचता था तो उसके लिए उसको कहा जाता था कि इतने परसैंट दे दो। अब हमें ये सारी व्यवस्थाएं बदलनी हैं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी शमशेर सिंह जी ने भी कहा और मैं भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं करती लेकिन यह भी हकीकत है कि गलत कार्यों की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जायेगा छोटे से लेकर बड़े तक किसी को बख्शा नहीं जायेगा। मेरे साथी कर्ण सिंह दलाल जी कह रहे थे कि हमारी सरकार किस प्रकार से दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी और इस बारे में सरकार की क्या नीति है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह बात आज यहां स्पष्ट करने वाली नहीं है अगर आज यह बात स्पष्ट कर दी तो जो दोषी हैं वे अपना बचाव ढूंढ लेंगे। समय पर सही तरीके से कार्यवाही होगी और हमारा प्रयास होगा कि कोई भी दोषी बच न सके। चक्की चलती है तो पीसती भी है लेकिन बारीक पीसने में थोड़ा समय लगता है। इसमें हम सभी का सहयोग लेंगे। हम बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। बदले की भावना से कार्यवाही करना कांग्रेस पार्टी की नीति भी नहीं है। पिछले 6 सालों का शासन एक युग था। हमारे लिए और प्रदेश की जनता के लिए युग का मतलब एक बुरा सपना था; भयानक सपना था। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस बुरे और भयानक सपने को भुलाना है और जो लोग दोषी हैं उनको दण्डित करना है। मेरी साथियों से प्रार्थना है कि सभी साथी रचनात्मक सुझावों के बारे में सोचें और उस भयानक सपने को भूल जायें और प्रदेश के हितार्थ कार्य करें। हमें इधर-उधर की बातों की तरफ ज्यादा ध्यान न देकर प्रदेश की भलाई के बारे में सोचना है और हमारी संस्थाओं की प्रतिष्ठा को कायम करने का कार्य करना है। आज मैं असैम्बली में हूं, पांच साल पहले भी रहा और पार्लियामैंट में भी रहा । इंदौरा साहब भी मेरे साथ पार्लियामैंट में रहे हैं और आज की इस असैम्बली में ऐसे 10 माननीय सदस्य हैं जो पार्लियामैंट में भी रहे हैं। हमारा सबका यह प्रयास रहेगा कि इस संस्था की, लैजिसलेचर की प्रतिष्ठा बनी रहे और इस प्रतिष्ठा को बनाये रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। हमारे अध्यक्ष जी बड़े काबिल और अनुभवी शख्सियत वाले हैं। इनकी देखरेख में सदन की गरिमा तथा प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सभी साथियों को अपने विचार रखने की खुली छूट होगी और सभी साथी रचनात्मक सुझाव दे सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की राजनीति में आज कांग्रेस पार्टी का शासन है और मैं उसका हैड हूं, मुख्यमंत्री हूँ। पहले ऐसा होता रहा है कि जो भी सदस्य अपना सुझाव देना चाहता था उसके सुझाव सुने नहीं जाते थे और चौटाला साहब की आंख

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

और उंगली के इशारे से ही सदस्यों को बोलने दिया जाता था। यदि कोई सदस्य जनता की बात यहां पर कहता था तो उसकी बात सुनी नहीं जाती थी। अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने न तो स्वयं कोई जनहित के कार्य किए और न ही दूसरों की बात सुनते थे। यदि वे जनहित के कार्य करते तो आज उनकी यह हालत न होती। यदि लोक सभा के चुनावों के बाद भी वे कुछ सीख लेते तो उनकी हालत इतनी बुरी नहीं होती कि वे विपक्ष के नेता भी न बन सकें। सरकार तो उनकी आनी नहीं थी। इस तरह की उनकी तानाशाही थी कि उनकी सरकार के समय में कोई भी सदस्य अपने विचार खुलकर नहीं रख सकता था। लेकिन उन्होंने अपने सदस्यों को यह छूट दे रखी थी कि वे हमें कुछ भी कहें, हमारे ऊपर व्यक्तिगत अटैक करें और हमारी तरफ से जब कोई सदस्य बोलता था तो उसे बोलने नहीं दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, वे ऐसा क्यों करते थे यह तो वे ही जाने लेकिन जो भी सदस्य चुनकर आया है उसे बोलने का अधिकार है। अपनी बात कहने और रचनात्मक सुझाव देना उसका अधिकार है। जहां तक मैं समझता हूं, वे यह सोचते थे कि यदि उनकी पार्टी का कोई सदस्य उनकी इच्छा के बगैर बोलेगा तो वह डिसीडैंट हो गया। इस तरह की उनकी तानाशाही प्रवृति थी। लेकिन अब हमें यह सब कुछ बदलना होगा इसी से हमारे प्रदेश का विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सभी सदस्य सरकार की नीतियों पर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकेंगे और रचनात्मक सुझाव दे सकेंगे। विपक्ष न के बराबर है। सभी अच्छे साथी चुनकर आये हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं इनके बिना प्रजातंत्र कायम नहीं हो सकता। मैं अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि विपक्ष का काम भी सत्तापक्ष को ही करना है। हमारा कोई भी साथी खुलकर रचनात्मक सुझाव दे सकता है और सरकार की आलोचना भी कर सकता है। जो भी साथी सही आलोचना करेगा मैं उसको निंजी आलोचना नहीं मानूंगा बल्कि उस बात को मैं एक सुधारक के रूप में ग्रहण करूंगा। हमारे साथी जो भी रचनात्मक सुझाव देंगे सरकार उन पर गम्भीरता से विचार करेगी जिससे प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। प्रदेश को पूरा लाभ तभी होगा जब हम पूरी व्यवस्था को बदलें और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ायें सही मायने में हाऊस में भी प्रजातंत्र कायम हो। आप सभी अपने अपने इलाके से चुन करके आएं हैं और लोगों को आपसे बहुत सी आशाएं और उम्मीदें भी हैं। लोगों ने आपको मान सम्मान के साथ चुन करके भेजा है। आपको यहां पर भी पूरा मान सम्मान मिलेगा। अगर आप ठीक कार्य करेंगे, रचनात्मक सुझाव देंगे सरकार उनको गंभीरता से लेगी तथा उन सुझावों पर अमल होगा। सभी साथियों की तरफ से बहुत सी बातें आयी हैं उनको अब मैं गिना नहीं सकता। मैं सभी साथियों की बातें गहराई से सुन रहा था। जिन साथियों ने रचनात्मक सुझाव दिएं हैं। हम उन सब सुझावों पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आपके माध्यम से सभी साथियों से निवेदन है कि जो प्रस्ताव चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया है उसको सर्वसम्मति से पास करें। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker: Question is—

"That an Address be presented to the Governor in the following terms:—

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha Assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address

which he has been pleased to deliver to the House on the 22nd March, 2005."

The motion was carried.

Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

वर्ष 2004-2005 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 2004-2005.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 2004-2005.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, Shri Shadi Lal Batra, Chairperson Committee on Estimates will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2004-2005.

Shri Shadi Lal Batra (Chairperson, Committee on Estimatee) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2004-2005.

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 23rd March, 2005.

*17.19 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. Wednesday, the 23rd March, 2005)

39938—H.V.S.—H.G.P., Chd.